

करेंट अफेयर्स

उत्तर प्रदेश

(संग्रह)



अक्तूबर 2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्त	र प्रदेश	4
6	PMUY लाभार्थियों को मुफ्त LPG रिफिल मिलेगा	
6	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों का प्रख्यापन	5
6	इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी	6
6	गायक छन्नूलाल मिश्र का निधन	7
6	भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण (ABC) प्रशिक्षण केंद्र	8
6	उत्तर प्रदेश में 'गुड सेमेरिटन' पहल शुरू	9
6	डायरेक्ट-सीडेड राइस (DSR) कॉन्क्लेव 2025	10
6	अभिधम्म दिवस	
9	मैलानी-नानपारा ट्रैक हेरिटेज रूट घोषित	13
9	मैलानी-नानपारा ट्रैक हेरिटेज रूट घोषित	15
6	IUCN द्वारा घड़ियाल का पहली बार 'ग्रीन स्टेटस' आकलन	
6	उत्तर प्रदेश ड्रोन सुरक्षा नीति	18
6	इंडो-गैंगेटिक मैदान (IGP) में पीएम2.5 स्तर	19
6	गोमती पुनर्जीवन मिशन	20
6	ऑपरेशन शिकंजा	22
6	उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया संक्रमण की दर में गिरावट	23
6	उत्तर प्रदेश में काऊ टूरिज्म को प्रोत्साहन	
6	रक्षा मंत्री ने भविष्य हेतु तैयार सशस्त्र बलों पर पुस्तक का विमोचन किया	
6	उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में 256 अपराधी ढेर	
6	उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 में स्थापित हुई 4,000 नई फैक्ट्रियाँ	27
6	उत्तर प्रदेश बनाएगा डिजिटल कृषि नीति	
6	उत्तर प्रदेश में पराली दहन पर अंकुश लगाने हेतु सब्सिडी योजना की शुरुआत	
6	उत्तर प्रदेश में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस	
6	गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन मिनी कुंभ के रूप में	
9	12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR 2.0 प्रारंभ	31

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ > 2025



UPSC क्लासरूम कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स





6	उत्तर प्रदेश में 'लर्निंग बाय डूइंग' मॉडल	32
6	उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक्स हब	33
6	उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक सुधार लागू	34
6	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना SAP में वृद्धि	35
6	लखनऊ में नौसेना शीर्य संग्रहालय	36
राष्ट	ट्रीय करेंट अफेयर्स	.38
9	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस	38
9	राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025	39
6	माई भारत मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च	41
6	श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती	
9	विश्व कपास दिवस 2025	42
9	विश्व पर्यावास दिवस	43
9	93वाँ वायुसेना दिवस	44
6	70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025	45
6	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस	
6	विश्व मानक दिवस	
6	भारत-दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास (IN–RoKN)	
9	विश्व खाद्य दिवस 2025	
9	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती	
9	विशाखापत्तनम में गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब	
6	समुद्र शक्ति का पाँचवाँ संस्करण	
6	संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्त्ता देशों के (UNTCC) प्रमुखों का सम्मेलन 2025	
9	पिंकी आनंद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त	
9	नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि	
9	अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस और '#23for23' पहल	
9	वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025	
9	पूर्वी तिमोर आसियान का 11वाँ सदस्य बना	
9	भौतिक वैज्ञानिक जयंत नार्लीकर को विज्ञान रत्न	
9	मोंथा चक्रवात	65
9	DFC पर यात्री ट्रेनों का परिचालन	
9	8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें स्वीकृत	
9	न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त	
9	राष्ट्रीय एकता दिवस	68

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें









उत्तर प्रदेश

PMUY लाभार्थियों को मुफ्त LPG रिफिल मिलेगा

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत होली और दिवाली के दौरान 1.86 करोड़ **लाभार्थी परिवारों** को दो मुफ्त **एलपीजी सिलेंडर** वितरित करने की स्वीकृति दी है।

 यह पहल मिहलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करती है, जिसमें मुफ्त रिफिल प्रदान करने की अनुमानित लागत 1,385.34 करोड़ रुपये है।

मुख्य बिंदु

💎 मुद्दे के बारे में:

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) को एक प्रमुख योजना के रूप में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं वंचित परिवारों को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराना है, जो अन्यथा लकडी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे।

💎 उद्देश्यः

- महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना।
- अशुद्ध खाना पकाने वाले ईंधन के कारण भारत में होने वाली मृत्यु दर को कम करना।
- छोटे बच्चों को गंभीर श्वसन रोगों से बचाना, जो घरेलू हवा के प्रदूषण के कारण होते हैं।

💎 विशेषताएँ:

- 🍥 इस योजना के तहत<u> BPL परिवारों</u> को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिये 1,600 रुपये की **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
- 🍥 जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ **उज्ज्वला 2.0** लाभार्थियों को पहला **रिफिल** और एक **हॉटप्लेट** निशुल्क प्रदान करेगी।

💎 लाभः

- पात्र लाभार्थियों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन मिलेगा।
- o लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडरों के पहले छह **रिफिल** या 5 किलोग्राम के सिलेंडरों के आठ **रिफिल** पर भी सब्सिडी मिलती
- लाभार्थी चूल्हे की लागत और रिफिल के भुगतान के लिये EMI सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं।
- लाभार्थी सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी राशि प्राप्त करने के लिये पहल योजना में भी शामिल हो सकते हैं।

PMUY के चरण:

 उज्ज्वला 1.0: 1 मई, 2016 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स





- 🌀 उज्ज्वला 2.0: शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिये सरकार ने अगस्त 2021 में उज्ज्वला 2.0 लॉन्च की।
 - ्र उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी परिवारों के लिये एक विशेष प्रावधान किया गया था, जिससे उन्हें पते के प्रमाण और राशन कार्ड की आवश्यकता के बजाय स्व-घोषणा के माध्यम से एक नया एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने की अनुमित मिली।

💎 उपभोग प्रवृत्तिः

वैश्विक स्तर पर PMUY इस प्रकार की सबसे बड़ी योजना है, जो 10.33 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को घरेलू एलपीजी प्रदान करती है और इसका प्रभावी मूल्य लगभग 35 रुपये/िकलोग्राम है।

💎 शीर्ष राज्य:

🧑 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान वे प्रमुख राज्य हैं, जो PMUY के कार्यान्वयन में अग्रणी हैं।

ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमों का प्रख्यापन

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश <u>मंत्रिमंडल</u> ने खनन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जारी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप उत्तर प्रदेश ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 के प्रख्यापन को स्वीकृति दी।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्यः संशोधन का उद्देश्य सामुदायिक विकास और कल्याणकारी गतिविधियों के लिये ज़िला खिनज फाउंडेशन (DMF) निधियों का उपयोग करके खनन कार्यों से सीधे प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को लाभान्वित करना है।
- निधि आवंटनः DMF निधि का 70% विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल,
 शिक्षा और कौशल विकास के लिये आवंटित किया जाएगा।
 - शेष 30% धनराशि का उपयोग भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि के लिये किया जा सकता है।
- वित्तीय प्रभाव: संशोधित नियमों के लागू होने से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
- निगरानी प्रणाली: PMKKKY के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा DMF निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी सिमिति गठित की जाएगी।

ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF)

- खान एवं खिनज विकास विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार, खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित प्रत्येक ज़िले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में एक ट्रस्ट की स्थापना करेगी जिसे ज़िला खिनज फाउंडेशन कहा जाएगा।
- DMF निधि: प्रत्येक खनन पट्टाधारक, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, DMF को रॉयल्टी का एक हिस्सा, जो कुल रॉयल्टी के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगा, का भुगतान करेगा।
- कार्यप्रणाली: DMF ट्रस्टों की कार्यप्रणाली और निधियों का उपयोग संबंधित राज्यों के DMF नियमों द्वारा शासित होता है तथा इसमें केंद्रीय दिशानिर्देश, PMKKKY के अधिदेश शामिल होते हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर मॉड्यूज कोर्म





हृष्टि लर्निंग 🍃



प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- ▼ नोडल मंत्रालय: वर्ष 2025 में शुरू की गई PMKKKY खनन मंत्रालय द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के तहत अर्जित धन का उपयोग करके लोगों और प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण के लिये एक योजना है।
- उद्देश्यः सरकारी योजनाओं के पूरक के रूप में खनन क्षेत्रों में कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना, प्रतिकूल प्रभावों को कम करना तथा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
- PMKKKY 2024 दिशानिर्देश: PMKKKY 2024 में यह अनिवार्य किया गया है कि DMF निधि का कम-से-कम 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर खर्च किया जाना चाहिये,जो खनन प्रभावित समुदायों के कल्याण को सीधे प्रभावित करते हैं।

इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश ने **इंस्पायर पुरस्कार मानक** (MANAK- मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज) **योजना** के तहत सर्वाधिक **नामांकन (2.8 लाख)** प्राप्त कर छात्र-नेतृत्व वाली नवाचार गतिविधियों में राष्ट्रीय मानक स्थापित किया।

मुख्य बिंदु

- उल्लेखनीय उपलब्धिः इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 2.8 लाख नामांकन दर्ज किये गए, जो योजना शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है तथा विगत वर्ष के 2.1 लाख से 70,000 अधिक है।
- समावेशी भागीदारी: सभी 75 जिलों से सिक्रय भागीदारी देखी गई, जिसमें माध्यमिक, जूनियर हाई स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका
 <u>विद्यालय</u>, कंपोज़िट और संस्कृत विद्यालयों के छात्र शामिल थे।
- 💎 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ज़िले: प्रतापगढ़ (7,085), प्रयागराज (6,929), लखनऊ (6,721), हरदोई (6,689), जौनपुर (5,930)।
- 💎 नामांकन में **देश के शीर्ष 50 ज़िलों** में उत्तर प्रदेश के 22 ज़िले शामिल हैं।
- 💎 राष्ट्रीय तुलना: उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान 1.41 लाख और कर्नाटक 1.01 लाख नामांकनों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- INSPIRE पुरस्कार मानक योजनाः
 - यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार तथा राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (NIF) भारत (DST की स्वायत्त संस्था) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित एक प्रमुख योजना है।
 - लक्षित समूहः कक्षा 6 से 12 तक के छात्र।
 - उद्देश्यः स्कूल के छात्रों में नवाचार, मौलिकता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना।
 - प्रिक्रियाः छात्र ऑनलाइन नामांकन के माध्यम से नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं।

इंस्पायर INSPIRE) योजना

INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक अवस्था से ही युवाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित करना तथा भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिक तंत्र को सशक्त बनाने के लिये एक मजबूत मानव संसाधन आधार का निर्माण करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेस

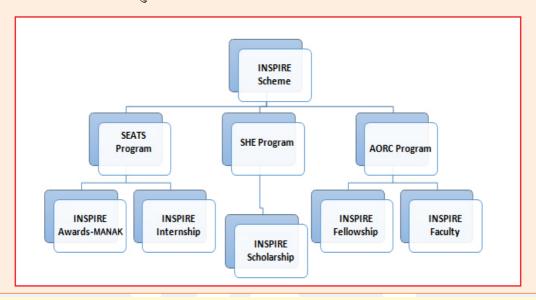


IAS करेंट अफेयर्स





भारत सरकार वर्ष 2010 से इंस्पायर योजना को क्रियान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत इंस्पायर पुरस्कार मानक सिहत पाँच घटकों के माध्यम से 10-32 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है।



गायक छन्नुलाल मिश्र का निधन

चर्चा में क्यों?

हिंदस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित छन्नुलाल मिश्र का लंबी बीमारी के बाद 89 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में निधन हो गया।

मुख्य बिंदु

- छन्नुलाल मिश्र के बारे में:
 - 💿 उनका जन्म ३ अगस्त, 1936 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के **हरिहरपुर** गाँव में हुआ था और 5 अक्तूबर, 2025 को उनका निधन हो गया।
- संगीत यात्राः
 - वह <u>हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत,</u> विशेष रूप से ख्याल, <u>ठुमरी</u>, दादरा, चैती, कजरी और भजन शैलियों के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक थे।
 - उन्होंने प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र से प्राप्त किया।
 - किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खान तथा ठाकुर जयदेव सिंह के मार्गदर्शन में उनकी शास्त्रीय संगीत शिक्षा और समृद्ध हुई।
 - उन्होंने <mark>बनारस घराने</mark> की **ख्याल, टुमरी** और **पूरब अंग शैलियों को** वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की।



'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













💎 पुरस्कारः

- संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार: 2000
- णद्म भूषण: 2010
- णद्म विभूषण: 2020

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत

- हिंदुस्तानी संगीत, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचिलत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य पद्धितयों में से एक है, दूसरा दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत है।
- उस मुख्यत: गायन-केंद्रित है, जिसमें ध्रुपद और ख्याल शास्त्रीय हिंदुस्तानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबिक ठुमरी, धमार, तराना, टप्पा, कव्वाली तथा गजल अर्द्ध-शास्त्रीय हिंदुस्तानी शैलिंगाँ हैं।

ठुमरी

💎 परिचयः

- यह उत्तर भारत का एक अर्ब्ध-शास्त्रीय संगीत रूप है, जो 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में उन्तत हुआ
- यह अपनी भावपूर्ण गहराई, माधुर्य और अभिव्यक्तिपूर्ण कहानी कहने की शैली के लिये प्रसिद्ध है।
- वर्ष 1856 में अवध के पतन के बाद इसका केंद्र बनारस में स्थानांतिरत हो गया, जहाँ इसे आध्यात्मिक और भिक्तपरक स्वर (राधा-कृष्ण थीम) मिला।

💎 विशेषताः

- इसमें राग नियमों के सख्त पालन के बजाय भाव (भावना) पर जोर दिया जाता है और सुधार तथा स्वतंत्रता की अनुमित दी जाती है।
- 💎 प्रभावः
 - इसमें होरी, कजरी, दादरा, झूला, चैती और अन्य लोक या अर्द्ध-शास्त्रीय रूपों के तत्त्व शामिल हैं।
- 💎 ठुमरी के रूप:
 - पूर्वी दुमरी (पूर्वी /धीमी गित): गीतात्मक और गहन भावनात्मक, मुख्यत: बनारस घराने से संबंधित।
 - पंजाबी ठुमरी (तीव्र गित): ऊर्जावान और जीवंत, पिटयाला घराने से संबंधित।
- 💎 प्रमुख घराने:
 - 🌀 बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना।

भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण (ABC) प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों?

लखनऊ नगर निगम (LMC) ने उत्तर प्रदेश के जरहरा में भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण (ABC) प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य आवारा कुत्तों के प्रबंधन में पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और ABC प्रशिक्षण के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडें





UPSC क्लासरूम कोर्मेस



IAS करेंट अफेयर्स





मुख्य बिंद

- साझेदारी: यह केंद्र LMC, भारतीय पश कल्याण बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच सहयोग का परिणाम है, जो ह्यमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है।
- **उद्देश्यः** इसका प्रमुख उद्देश्य **आवारा कुत्तों की नसबंदी कार्यक्रमों** को सशक्त बनाना तथा पशु कल्याण विधियों में सुधार करना है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमः केंद्र 15 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों घटक शामिल हैं। प्रतिभागी कृत्तों की देखभाल, एनेस्थीसिया देने, नसबंदी तकनीकों एवं शल्यक्रिया के बाद की देखभाल में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे।
- लक्षित वर्गः यह प्रशिक्षण पश् चिकित्सकों, सहायक पश् चिकित्सकों, पश् संचालकों तथा आवारा कृत्तों के प्रबंधन में शामिल **संगठनों** के लिये खुला है।
- प्रमाण-पत्र: प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा, जो उनकी मानवीय एवं प्रभावी ABC प्रक्रियाओं के संचालन हेत् तत्परता को प्रमाणित करेगा।

उत्तर प्रदेश में 'गुड सेमेरिटन' पहल शुरू

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'गुड सेमेरिटन' पहल के तहत 'राहवीर' नामक सहायकों के लिये एक पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों को "सुनहरे घंटे" (Golden Hour) के भीतर अस्पताल पहँचाने में सहायता करते हैं।

- यद्यपि यह पहल <mark>केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय</mark> द्वारा तैयार की गई है, लेकिन दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिये इसे पूरे भारत में राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- <u>मोटर वाहन अधिनियम, 1988</u> के अनुसार, 'गुड सेमेरिटन' वह व्यक्ति होता है, जो सद्भावनापूर्वक तथा बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के दुर्घटना के बाद **आपातकालीन चिकित्सकीय या गैर-चिकित्सकीय सहायता प्रदान करता है** या पीड़ितों को अस्पताल तक पहुँचाता है।

मुख्य बिंद्

- - यह योजना उन व्यक्तियों को मान्यता देती है और पुरस्कृत करती है जो "गोल्डन ऑवर" के दौरान प्रथम प्रतिक्रियाकारक (First Responder) के रूप में कार्य करते हैं।
 - ् गोल्डन ऑवर किसी आघात के तुरंत बाद का पहला महत्त्वपूर्ण घंटा होता है, जब तत्काल चिकित्सकीय सहायता से जान बचाई जा सकती है।
 - 🍥 वर्ष 2023 में, **सड़क दुर्घटनाओं** में 1.5 मिलियन लोगों की **मृत्यु हो** गई। इनमें से कई की **जीवन रक्षा संभव थी** यदि उन्हें **गोल्डन ऑवर** के भीतर शीघ्र चिकित्सा सुविधा मिल जाती।
 - गोल्डन ऑवर की अवधारणा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(12A) के तहत स्थापित की गई है, जो तात्कालिक चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाती है।
- सम्मान और पुरस्कार:
 - प्रत्येक घटना के प्रथम **प्रतिक्रियाकर्त्ता** को 'राहवीर' प्रमाण-पत्र के साथ 25,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













यदि एक से अधिक प्रतिक्रियाकर्त्ता किसी पीडि़त की सहायता करते हैं, तो पुरस्कार राशि समान रूप से वितरित की जाएगी।

💎 पात्रताः

- यह योजना मोटर वाहनों से संबंधित बड़ी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होती है, जहाँ पीड़ितों को गंभीर चोटें आती हैं, जिसके लिये उन्हें तीन दिन से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता होती है या वे मिस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित होते हैं।
- यदि उपचार के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो भी प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता पुरस्कार के पात्र होंगे।

💎 पारदर्शिता और सत्यापन:

- उत्तर प्रदेश पुलिस अस्पताल के सहयोग से प्रत्येक बचावकर्त्ता के विवरण का सत्यापन करेगी।
- पुष्टि के पश्चात्, जिला स्तर की सिमिति, जिला मिजस्ट्रेट की अध्यक्षता में, मान्यता-पत्र जारी करेगी और पुरस्कार प्रक्रिया को संपन्न करेगी।

💎 प्रभावः

- इस पहल से अधिक नागरिकों को बिना कानूनी जटिलताओं या हिचिकचाहट के दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिये प्रेरित करने की उम्मीद है।
- पहले अनेक लोग पुलिस या कानूनी समस्याओं के डर से मदद करने से बचते थे।
 - ्र <mark>राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2023</mark> के अनुसार, उत्तर प्रदेश मे**ं** भारत में सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मृत्यु दर्ज की गईं, वर्ष 2023 में 22,532 मृत्यु हुईं, जो राष्ट्रीय सड़क मृतकों का 14% है।

डायरेक्ट-सीडेड राइस (DSR) कॉन्क्लेव 2025

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (ISARC) में आयोजित डायरेक्ट-सीडेड राइस (DSR) कॉन्क्लेव 2025 में उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप वर्ष 2030 तक वैश्विक खाद्य भंडार बनने के लक्ष्य की पृष्टि की।

मुख्यमंत्री ने कृषि में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिये नए कृषि ज्ञान उत्पादों तथा यांत्रिकी नवाचारों
 का शुभारंभ किया एवं किसानों को मिनी किट वितरित की।

मुख्य बिंदु

- 💎 कॉन्क्लेव के बारे में:
 - यह नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिये एक मंच है, जहाँ वे उत्तर प्रदेश तथा उसके बाहर अनुकूल, समावेशी एवं जलवायु-संवेदनशील कृषि विकास के लिये क्रियान्वयन योग्य मार्ग तलाश करते हैं।
- 💎 वैश्विक खाद्य भंडार विजन:
 - मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव के दौरान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की 150वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में सतत्, जलवायु-संवेदनशील और प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि परिवर्तनों पर जोर दिया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर





- П
- उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों (CGIAR) के संघ को सहयोग देने की राज्य की महत्त्वाकांक्षा पर जोर दिया, जिसमें
 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) और अंतर्राष्ट्रीय आल केंद्र (CIP) जैसे साझेदार शामिल हैं।
- ये सहयोग उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर खाद्य उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाएंगे।

💎 कृषि प्रगति और उपलब्धियाँ:

- उत्तर प्रदेश भारत के खाद्य उत्पादन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जो देश के कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 11% होने के बावजूद राष्ट्रीय
 उत्पादन में 21% का योगदान देता है।
- विगत आठ वर्षों में राज्य सरकार के प्रयासों के कारण कृषि-खाद्य उत्पादन में पाँच गुना वृद्धि हुई है, विशेष रूप से अनाज, दालें,
 तिलहन और सिब्ज़ियों में।
- यह सफलता राज्य द्वारा संचालित पहलों, जैसे- मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल बीमा तथा किसान सम्मान निधि योजना का परिणाम
 है, जिससे प्रतिवर्ष 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है।

💎 क्षमता निर्माण:

राज्य में चार कृषि विश्वविद्यालय हैं तथा एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना है। ये विश्वविद्यालय अनुसंधान, प्रशिक्षण
 और ज्ञान-साझाकरण प्रयासों के केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं एवं कृषि परिवर्तन को गित दे रहे हैं।

💎 पारंपरिक कृषि ज्ञानः

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तर पर्देश की समृद्ध कृषि परंपराएँ, जैसे प्रतिष्ठित काला नमक चावल, जो एक जिला एक उत्पाद पहल का हिस्सा है, ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं। क्योंिक इसे भगवान बुद्ध द्वारा महाप्रसाद के रूप में अर्पित किया गया था।

अभिधम्म दिवस

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (IBC) ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से 6-7 अक्तूबर, 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस मनाया।

मुख्य बिंदु

अभिधम्म दिवस के बारे में:

- यह दिवस उस अवसर को स्मरण करता है जब बुद्ध ने अपनी माता महामाया के नेतृत्व में तावितंस-देवलोक के देवताओं को अभिधम्म का उपदेश दिया था और बाद में इसे अपने शिष्य अरहंत सारिपुत्त के साथ साझा किया।
- यह दिन भगवान बुद्ध के तैंतीस दिव्य जीवों (तावितंस देवलोक) के स्वर्गलोक से उत्तर प्रदेश के संकितया (संकिसा बसंतपुर, फर्रुखाबाद) में अवतरण का भी स्मरण कराता है।
- इस स्थान का महत्त्व यहाँ स्थित अशोक के हाथी स्तंभ की उपस्थिति से प्रदर्शित होता है।

💎 घटना का प्रतीक:

🍥 अभिधम्म दिवस का आयोजन वर्षावास (वस्सा) और पवारणा उत्सव के समापन के अवसर पर किया जाता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयल कोर्म







- ् वर्षावास (वस्सा): यह एक वार्षिक तीन महीने का मठवासी एकांतवास है, जो विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान <mark>थेरवाद</mark> बौद्ध परंपरा में किया जाता है।
- ् पवारणा उत्सव: यह वस्सा के समापन का प्रतीक है, जहाँ भिक्षु एकत्र होकर एकांतवास के दौरान हुई किसी भी गलती या भूल को स्वीकार करते हैं और अपने साथी भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं कि वे उन किमयों को इंगित करें जो उन्होंने देखी हों। यह उत्सव 11वें चंद्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्तूबर में आता है।

💎 मुख्य क्रियाएँ:

- आधुनिक संदर्भ में अभिधम्म के दार्शनिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करने के लिये "बौद्ध विचार को समझने में अभिधम्म की प्रासंगिकताः पाठ, परंपरा तथा समकालीन परिप्रेक्ष्य" पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- विनोद कुमार द्वारा क्यूरेट की गई 90 देशों की 2,500 से अधिक बौद्ध डाक टिकटों की एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें डाक टिकट संग्रह के माध्यम से बौद्ध विरासत की झलक प्रस्तुत की गई।
 - ् दो विषयगत प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं,जिनमें "शरीर और मन पर बुद्ध धम्म" तथा पिपरहवा अवशेषों पर प्रकाश डालने वाली एक प्रदर्शनी शामिल थी, जिसमें बुद्ध की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला गया।
- इस कार्यक्रम में दो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया "एशिया में बुद्ध धम्म का प्रसार" और "कुशोक बकुला रिनपोछे एक असाधारण भिक्षु की अद्भुत कहानी", जिसका निर्देशन डॉ. हिंडोल सेनगुप्ता ने किया था।

अभिधम्म पिटक

- अभिधम्म पिटक तीन पिटकों में अंतिम है, जो पाली कैनन/त्रिपिटक का हिस्सा है और थेरवाद बौद्ध धर्म के सबसे लोकप्रिय ग्रंथों में से एक है।
 - यह सुत्तों में दिये गए बुद्ध के उपदेशों का विस्तृत शास्त्रीय विश्लेषण और सारांश प्रस्तुत करता है।
 - 🍥 इसमें **बौद्ध धर्म का दर्शन, सिद्धांत, मनोविज्ञान, दार्शनिक तर्क, नैतिकता और ज्ञानमीमांसा** शामिल है।
- 💎 त्रिपिटक के अन्य शेष पिटक विनयपिटक और सुत्तपिटक हैं।
 - विनयिपटक में संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिये आचरण के नियम हैं।
 - सुत्तिपिटक में बुद्ध और उनके निकट शिष्यों द्वारा दिये गए सुत्त (शिक्षाएँ/प्रवचन) शामिल हैं।
- 💎 अभिधम्म पिटक में सात पुस्तकें हैं:
 - धम्मसंगणि- घटनाओं की गणना
 - विभंग- संधियों की पुस्तक
 - धातुकथा- तत्त्वों के संदर्भ में चर्चा
 - 🌀 पुग्गलापनट्टी (Puggalapanatti)- व्यक्तित्व का विवरण
 - कथावत्थु- विवाद के बिंदु
 - यमाका- पुस्तकों का युग्म
 - पथना (Patthana) -संबंधों की पुस्तक
- भारत सरकार ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है तथा अभिधम्मिपटक सिंहत थेरवाद बौद्ध ग्रंथों की प्रामाणिक भाषा के रूप में इसके

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर







मैलानी-नानपारा ट्रैक हेरिटेज रूट घोषित

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली 171 किमी. लंबी मैलानी-नानपारा मीटर गेज रेल लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025



UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयल कोर्स







मुख्य बिंदु

- मैलानी-नानपारा मीटर गेज रेलवे लाइन, जिसका निर्माण लगभग 130 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों द्वारा कई चरणों में किया गया था, में 16 स्टेशन, 71 पुल और मैलानी तथा नानपारा पर अद्वितीय दोहरे गेज स्टेशन शामिल हैं।
- प्रथम संरक्षित मीटर गेज लाइन: यह पूर्वोत्तर रेलवे (NER) की पहली मीटर गेज लाइन है, जिसे संरक्षित किया गया है तथा इसे ब्रॉड गेज में पिरवर्तित करने के बजाय इसके मौलिक रूप (नैरो गेज) को बनाए रखा गया है।
- सतत् पर्यटन मॉडलः पूर्वोत्तर रेलवे ने मैलानी और दुधवा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर पारंपिरक रेलवे उपकरणों को संरक्षित रखने तथा मीटर
 गेज डीज़ल इंजनों को समर्पित सुविधाओं पर बनाए रखने की योजना बनाई है।
- हेरिटेज टूरिज़्म का शुभारंभ: वर्ष 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मैलानी-बिछिया AC टूरिस्ट कोच का शुभारंभ किया गया, जिससे इस क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज़्म की शुरुआत हुई।
 - इस नए हेरिटेज दर्जे से पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा, क्षेत्रीय संपर्क में सुधार तथा स्थानीय आजीविका को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

💎 अन्य प्रमुख घटनाक्रमः

- लखीमपुर-मैलानी ब्रॉड गेज खंड के पीलीभीत तक विस्तार से मैलानी जंक्शन अब हेरिटेज और आधुनिक रेलवे संरचना के बीच एक कड़ी बन गया है।
- हाल ही में नानपारा जंक्शन के माध्यम से बहराइच से नेपालगंज रोड खंड को भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रॉड-गेज ट्रैक के रूप में चालू किया गया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में और वृद्धि हो गई है।
- अप्रैल 2025 में गोरखपुर जंक्शन के 140 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैलानी से दुधवा तक विशेष हेरिटेज पर्यटक ट्रेन संचालित की गई।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान

💎 स्थापनाः

- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में
 490 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में विस्तृत एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में की गई थी।
- दलदली हिरण (बारहसिंगा) की आबादी को विलुप्त होने से बचाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1958 में इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया।
- वर्ष 1977 में इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया तथा वन्यजीव संरक्षण उपायों को सशक्त करने के लिये इसमें अतिरिक्त क्षेत्र भी शामिल किये गए।
- इस पार्क को वर्ष 1987 में टाइगर रिज़र्व भी घोषित किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में बंगाल टाइगर्स की उल्लेखनीय आबादी पाई जाती है।

💎 जैवविविधताः

- इस पार्क में जीवों की एक समृद्ध विविधता है, जिसमें बंगाल टाइगर, तेंदुए, हाथी, भालू, भारतीय गैंडे और 450 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं।
 - ्र इसके पारिस्थितिक तंत्र में <mark>घास के मैदान</mark>, दलदल और तराई क्षेत्र के विशिष्ट घने साल के जंगल शामिल हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर





💎 संरक्षणः

- 🧑 प्रमुख पहलों में **आवास पुनर्स्थापन** और दलदली हिरण तथा बारहसिंगा जैसी **लुप्तप्राय प्रजातियों का पुनःप्रवेश शामिल है।**
- उद्यान की जैविविविधता को संरक्षित करते हुए सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु
 ईको-टूरिज़्म कार्यक्रम संचालित किये गए हैं।

मैलानी-नानपारा ट्रैक हेरिटेज रूट घोषित

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली 171 किमी. लंबी मैलानी-नानपारा मीटर गेज रेल लाइन को हेरिटेज रूट घोषित किया गया है।

मुख्य बिंदु

- मैलानी-नानपारा मीटर गेज रेलवे लाइन, जिसका निर्माण लगभग 130 वर्ष पूर्व अंग्रेज़ों द्वारा कई चरणों में किया गया था, में 16 स्टेशन, 71 पुल और मैलानी तथा नानपारा पर अद्वितीय दोहरे गेज स्टेशन शामिल हैं।
- प्रथम संरक्षित मीटर गेज लाइन: यह पूर्वोत्तर रेलवे (NER) की पहली मीटर गेज लाइन है, जिसे संरक्षित किया गया है तथा इसे ब्रॉड गेज में पिरवर्तित करने के बजाय इसके मौलिक रूप (नैरो गेज) को बनाए रखा गया है।
- सतत् पर्यटन मॉडलः पूर्वोत्तर रेलवे ने मैलानी और दुधवा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर पारंपिरक रेलवे उपकरणों को संरक्षित रखने तथा मीटर
 गेज डीज़ल इंजनों को समर्पित सुविधाओं पर बनाए रखने की योजना बनाई है।
- हेरिटेज टूरिज़्म का शुभारंभ: वर्ष 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मैलानी-बिछिया AC टूरिस्ट कोच का शुभारंभ किया गया, जिससे इस क्षेत्र में हेरिटेज टूरिज़्म की शुरुआत हुई।
 - इस नए हेरिटेज दर्जे से पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा, क्षेत्रीय संपर्क में सुधार तथा स्थानीय आजीविका को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

💎 अन्य प्रमुख घटनाक्रमः

- लखीमपुर-मैलानी ब्रॉड गेज खंड के पीलीभीत तक विस्तार से मैलानी जंक्शन अब हेरिटेज और आधुनिक रेलवे संरचना के बीच
 एक कड़ी बन गया है।
- हाल ही में नानपारा जंक्शन के माध्यम से बहराइच से नेपालगंज रोड खंड को भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रॉड-गेज ट्रैक के रूप में चालू किया गया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में और वृद्धि हो गई है।
- अप्रैल 2025 में गोरखपुर जंक्शन के 140 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैलानी से दुधवा तक विशेष हेरिटेज पर्यटक ट्रेन संचालित की गई।

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान

💎 स्थापनाः

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1977 में 490 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में विस्तृत एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयल कोर्म



दृष्टि लर्निंग[े]



- दलदली हिरण (बारहसिंगा) की आबादी को विलुप्त होने से बचाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1958 में इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया।
- वर्ष 1977 में इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया तथा वन्यजीव संरक्षण उपायों को सशक्त करने के लिये इसमें अतिरिक्त क्षेत्र भी शामिल किये गए।
- इस पार्क को वर्ष 1987 में टाइगर रिज़र्व भी घोषित किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में बंगाल टाइगर्स की उल्लेखनीय आबादी पाई जाती है।

💎 जैवविविधताः

- इस पार्क में जीवों की एक समृद्ध विविधता है, जिसमें बंगाल टाइगर, तेंदुए, हाथी, भालू, भारतीय गैंडे और 450 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं।
 - ्र इसके पारिस्थितिक तंत्र में घास के मैदान, दलदल और तराई क्षेत्र के विशिष्ट घने साल के जंगल शामिल हैं।

💎 संरक्षणः

- प्रमुख पहलों में आवास पुनर्स्थापन और दलदली हिरण तथा बारहिसंगा जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का पुन:प्रवेश शामिल है।
- उद्यान की जैविविविधता को संरक्षित करते हुए सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु
 ईको-ट्रिज़्म कार्यक्रम संचालित किये गए हैं।

IUCN द्वारा घड़ियाल का पहली बार 'ग्रीन स्टेटस' आकलन

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने घड़ियाल (Gavialis Gangeticus) की पहली 'ग्रीन स्टेटस' (Green Status) का आकलन जारी किया है।

 प्रजाति को लगातार संरक्षण प्रयासों के बावजूद जारी खतरों के कारण "गंभीर रूप से क्षीण" (Critically Depleted) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मुख्य निष्कर्ष

💎 आवास:

- चंबल नदी (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग 500 िकमी. तक विस्तृत है) घड़ियालों का अंतिम प्रमुख आश्रय
 स्थल बनी हुई है, जहाँ कई हज़ार घड़ियाल पाए जाते हैं।
 - ् <u>चंबल अभयारण्य</u> (1979 में स्थापित) वन में घड़ियालों की प्रजनन योग्य संख्या वाला एकमात्र स्थल है। यह अभयारण्य गंगा नदी डॉल्फिन और रेड-क्राउन रूफ्ड टर्टल जैसी अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों का भी संरक्षण करता है।
 - अन्य संख्याएँ केवल उत्तर भारत और नेपाल में छोटे तथा पृथक् क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं।
- <u>विश्व वन्यजीव कोष (WWF) इंडिया</u> की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 0.5% युवा घड़ियाल ही वयस्क अवस्था तक जीवित रहते हैं, जो उनके घोंसले बनाने वाले आवासों की सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिससे उनकी पुनर्प्राप्ति में सहायता मिल सके।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम

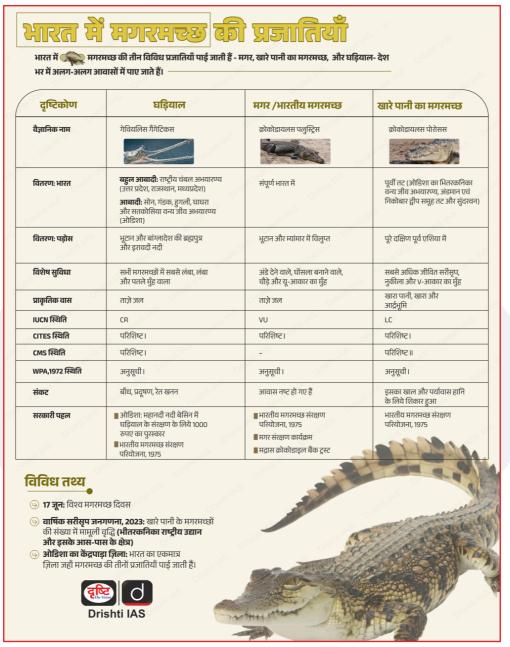


IAS करेंट अफेयर्स









ऐतिहासिक क्षेत्र और ह्रासः एक समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सिंधु और इरावती जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों में व्यापक रूप से पाए जाने वाले घड़ियालों को बड़े पैमाने पर बालू खनन, शिकार (पशुओं की खाल के लिये), अंडों का संग्रह, बांधों तथा बैराजों के निर्माण के कारण तेज़ी से आवासीय विनाश का सामना करना पड़ा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर







- \circ 1970 के दशक तक यह प्रजाति अपने ऐतिहासिक क्षेत्र के लगभग 98% क्षेत्र से विलुप्त हो चुकी थी।
- 🌀 वर्तमान अनुमान के अनुसार वन में लगभग **681 वयस्क घड़ियाल** बचे हैं, जिनमें से **80% चंबल नदी** में आवास करते हैं।
- IUCN 'ग्रीन स्टेटस' बनाम रेड लिस्ट: IUCN ग्रीन स्टेटस पारंपिक रेड लिस्ट से भिन्न है, क्योंकि इसमें केवल विलुप्त होने के जोखिम के बजाय पूर्ण पारिस्थितिक पुनर्प्राप्ति (Full Ecological Recovery) की दिशा में प्रगित का आकलन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ड्रोन सुरक्षा नीति

चर्चा में क्यों?

पिछले चार महीनों के दौरान, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बिना **अनुमित के ड्रोन उड़ाने या 'ड्रोन गैंग'** के संबंध में अफवाहें फैलाने के मामलों में कई प्र<mark>थम सूचना रिपोर्ट (FIR)</mark> दर्ज की गईं और कई व्यक्तियों को **गिरफ्तार** किया गया।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: इस नीति का उद्देश्य ड्रोन संचालन की सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये ज़िला तथा आयुक्तालय स्तर (Com-missionerate Level) पर सख्त निगरानी एवं नियमों का पालन करना है।
- ड्रोन निगरानी और पंजीकरण रजिस्टर: हर जिले को यह सुनिश्चित करना है कि सभी पंजीकृत ड्रोन, उनके ऑपरेटर और स्थानीय
 रिपेयर केंद्रों का विवरण समर्पित रजिस्टर में दर्ज तथा ट्रैक किया जाए।
- 💎 ड्रोन निगरानी समितियाँ:
 - अध्यक्षः जिले स्तर की ड्रोन सिमिति की अध्यक्षता जिला मिजस्ट्रेट (DM) करेंगे।
 - सदस्य: सिमिति में विरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) या पुलिस अधीक्षक (SP) और अतिरिक्त ज़िला मिजस्ट्रेट (ADM)
 सदस्य होंगे।
 - जिम्मेदारियाँ: सिमिति का कार्य ड्रोन संचालन की निगरानी, नियमों का पालन सुनिश्चित करना और अनिधकृत उपयोग के मामलों
 का निवारण करना है।
- सीमित हवाई क्षेत्र के लिये रेड जोन:
 - अस्थायी रेड जोनः आवश्यकतानुसार, जिला स्तर की सिमित अस्थायी रेड जोन घोषित करने का अधिकार रखती है।
 - अविधः रेड जोन अधिकतम 96 घंटे तक प्रभावी रहेंगे और इन्हें डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर चिह्नित किया जाएगा।
- 💎 स्थानीय खुफिया और जागरूकता अभियान:
 - खुिफिया नेटवर्क: ड्रोन से संबंधित अफवाहों को रोकने के लिये स्थानीय खुिफिया नेटवर्क और सोशल मीडिया निगरानी सिक्रिय की जाएगी।
 - सार्वजनिक जागरूकता: जनता को वैध ड्रोन गितिविधियों के संबंध में शिक्षित करने के लिये UP-112 और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाएँगे।
 - तत्काल पुलिस प्रतिक्रियाः ड्रोन गितविधियों से संबंधित किसी भी शिकायत या चिंता पर पुलिस की त्विरित प्रतिक्रिया सुनिःश्चित की जाएगी।
- ऑनलाइन ड्रोन पंजीकरण पोर्टल: राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में संचालित सभी ड्रोन के पंजीकरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करेगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर्स





- सभी **ड्रोन ऑपरेटरों को इस प्लेटफॉर्म पर अपने विवरण घोषित करना अनिवार्य** होगा और ये विवरण **स्थानीय पुलिस थाने में** दर्ज किये जाएँगे।
- प्रत्येक पुलिस थाना को स्थानीय रिजस्टर में ड्रोन के रिजस्ट्रेशन नंबर, स्वामित्व विवरण और स्थानीय मैकेनिक की जानकारी दर्ज करनी होगी।
- **दंड:** अनिधकृत ड्रोन संचालन पर **ड्रोन नियम, 2021** और लागू **आपराधिक कानूनों** के अनुसार **कड़ी सज़ा** दी जाएगी।
- सहयोग और समन्वयः किसी भी संदेहास्पद हवाई खतरे की स्थिति में पुलिस तुरंत वायुसेना ऑपरेशन रूम और सिविल एविएशन निदेशालय को सूचित करेगी।
- सर्वे अधिसूचना: स्थानीय पुलिस थाना को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी ड्रोन सर्वेक्षण की अनुमित नहीं होगी।

इंडो-गैंगेटिक मैदान (IGP) में पीएम2.5 स्तर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा पर आधारित है। इस रिपोर्ट में वाराणसी को 17 शहरों में से सबसे स्वच्छ और कोलकाता को **तीसरे सबसे स्वच्छ शहर** के रूप में स्थान दिया गया है, जो कि इंडो-गैंगेटिक मैदान (IGP) में PM2.5 सांद्रता के संदर्भ में है।

मुख्य बिंदु

- शहरों की पीएम2.5 स्तर के अनुसार रैंकिंग:
 - वाराणसी: IGP के शहरों में सबसे कम पीएम2.5 सांद्रता के साथ सूची में शीर्ष पर।
 - सिलीगुड़ी और प्रयागराज: पीएम2.5 स्तर के मामले में दूसरे स्थान पर समान रैंक।
 - कोलकाता: IGP में तीसरे स्थान पर, जो अन्य कई शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत स्वच्छ वायु को दर्शाता है।
 - गाज़ियाबाद: IGP का सबसे प्रदूषित शहर, जहाँ प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है।
- भौगोलिक और मौसमीय कारक: इंडो-गैंगेटिक मैदान (IGP) एक वैश्विक स्तर का वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट है, जो घनी जनसंख्या, उच्च मानव गतिविधियाँ और अनुकूल नहीं मौसमीय परिस्थितियों के संयोजन के कारण होता है।
 - इस क्षेत्र में PM2.5 और अन्य प्रदूषकों की उच्च स्तर की सांद्रता पाई जाती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जीवन प्रत्याशा पर गंभीर प्रभाव डालती है।
 - कोलकाता, जो IGP के पूर्वी छोर पर स्थित है, में सिमा-पार वायु प्रदूषण का अनुभव होता है, जो आमतौर पर गंगीय घाटी के उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर प्रवाहित होता है और शहर के प्रदूषण भार में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता अनुपालन: CREA अध्ययन में शामिल भारत के 235 शहरों में, नंदेसरी (गुजरात) ने सबसे निम्नस्तरीय पीएम2.5 सांद्रता **89 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर** दर्ज की, जबकि **करवार (कर्नाटक)** सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सामने आया, जहाँ पीएम2.5 केवल 4 माइक्रोग्राम था।
 - दिल्ली को राष्ट्रीय स्तर पर 28वाँ स्थान मिला, जहाँ पीएम2.5 का स्तर 36 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ मध्यम प्रदूषण के श्रेणी में है।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें











- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम: इस कार्यक्रम में शामिल 93 शहरों, जिनमें कोलकाता भी शामिल है, ने राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता <u>मानक (National Ambient Air Quality Standard-NAAQS)</u> 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर को पूरा किया, जो वायु गुणवत्ता में सुधार की सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
 - हालाँकि, केवल 32 शहरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के अधिक सख्त मानक का पालन किया।

वायु प्रदूषण

- परिचयः वायु प्रदूषण में ठोस, द्रव, गैस, ध्विन और रेडियोधर्मी विकिरण का वातावरण में ऐसा होना शामिल है, जिसकी सांद्रता मनुष्यों, जीव-जंतुओं, संपत्ति या पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के लिये हानिकारक हो।
 - ये पदार्थ, जिन्हें प्रदूषक कहा जाता है, प्राकृतिक या मानव-निर्मित हो सकते हैं और विभिन्न स्रोतों द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे:
 औद्योगिक प्रक्रियाएँ, वाहनों के उत्सर्जन, कृषि गितिविधियाँ, प्राकृतिक घटनाएँ, जैसे वनाग्नि और ज्वालामुखी विस्फोट।
- कणीय पदार्थ (Particulate Matter- PM): PM वायु में अत्यंत सूक्ष्म कणों और द्रव बूँदों के मिश्रण को दर्शाता है। ये कण विभिन्न आकारों में होते हैं तथा सैकडों अलग-अलग यौगिकों से बने हो सकते हैं।
 - PM10 (सहजीव कण/Coarse particles): 10 माइक्रोमीटर या उससे निम्न व्यास वाले कण।

गोमती पुनर्जीवन मिशन

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ ने 'गोमती पुनर्जीवन मिशन' (Gomti Rejuvenation Mission)** की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य **गोमती नदी के अबाध प्रवाह और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन** को सुनिश्चित करना है।

इस मिशन का लक्ष्य नदी में मिलने वाले शहरी सीवेज के 95% प्रवाह को रोकना है, जो गोमती नदी के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

- दायरा एवं उद्देश्यः यह मिशन पीलीभीत से गाज़ीपुर तक पूरे नदी बेसिन को कवर करता है, तािक गोमती नदी को उसकी स्वच्छ, अविरल और प्राकृतिक अवस्था में पुनर्स्थापित किया जा सके।
- 💎 प्रस्तावित कदमः
 - 🏿 अतिरिक्त नालों को मौजूदा <mark>सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP)</mark> की ओर मोड़ा जाएगा।
 - नए उपचार संयंत्र स्थापित किये जाएंगे और पुराने संयंत्रों का उन्नयन किया जाएगा।
 - 🧑 नदी की समुचित सफाई और निगरानी सुनिश्चित करने के लिये **ट्रैक बोट्स, फ्लोटिंग बैरियर्स** तथा **एक्सकैवेटर्स** तैनात किये जाएँगे।
 - अवैध निर्माणों से उत्पन्न अतिक्रमण और प्रवाह में कमी की समस्या को दूर करने के लिये, नदी के प्राकृतिक मार्ग की बहाली हेतु ज़िला-विशिष्ट कार्ययोजनाएँ तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं।
- 💎 उद्देश्य:
 - नए वेटलैंड्स का निर्माण, जैसे- लखनऊ में एकाना वेटलैंड और सजन लेक।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर मॉड्यूज कोर्म

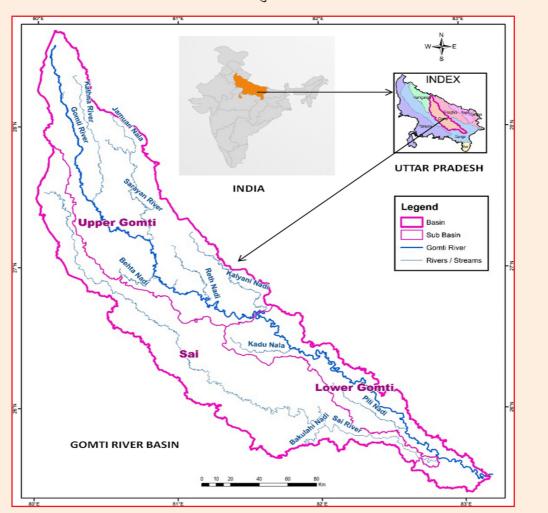






गोमती नदी

- गोमती नदी <u>गंगा नदी</u> की एक **960 किमी. लंबी उपनदी** है।
- यह **पीलीभीत ज़िले के मधो टांडा** से निकलती है और **गाज़ीपुर के कैथी** में गंगा से मिल जाती है।



- अतिक्रमण हटाने, घाटों की सजावट तथा हरित गिलयारों के प्रचार-प्रसार के लिये अभियान।
- नदी में प्रदूषण और सीवर ब्लॉकेज को रोकने के लिये **सिंगल-यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंध** का कड़ाई से पालन।
- इसे एक जन आंदोलन बनाने के लिये शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं के मार्गदर्शन में **सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम**।
- प्रशासनिक ढाँचाः गोमती टास्क फोर्स, जिसे जनवरी 2025 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के अंतर्गत गठित किया गया, इस मिशन के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेगा।

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

मेन्स टेस्ट सीरीज़











- इसमें स्टेट क्लीन गंगा मिशन, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम, लखनऊ नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हैं, साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञ भी इसमें भाग लेंगे।
- निगरानी तंत्र: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि:
 - गोमती टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएँ।
 - त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाएँ।
 - कार्य में अविरलता सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया जाए।
- वर्तमान स्थिति: नदी में कुल 39 प्रमुख नाले गिरते हैं, जिनमें से 13 का उपचार नहीं हुआ है, जबिक नदी के मार्ग में वर्तमान में छह
 STP संचालन में हैं।

ऑपरेशन शिकंजा

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश पुलिस के **आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW)** ने 9 से 13 अक्तूबर, 2025 तक **'ऑपरेशन शिकंजा'** चलाया, जिसके तहत राज्य भर में **23 फरार आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार** किया गया।

मुख्य बिंदु

- 💎 उद्देश्य:
 - उत्तर प्रदेश में बड़े वित्तीय घोटालों में लिप्त लंबे समय से फरार अपराधियों को पकडना।
 - गबन की गई सार्वजनिक धनराशि की जवाबदेही सुनिश्चित करना और उसकी वसूली करना।
 - 🌀 समन्वित पुलिसिंग के माध्यम से **श्वेतपोश (White-Collar) <u>अपराधों</u> के विरुद्ध कानून** के शासन को सुदृढ़ करना।
- समन्वयः महानिदेशक नीरा रावत के निर्देशों के तहत आठ विशेषीकृत टीमों ने डिजिटल इंटेलिजेंस के सहयोग से एक साथ कई ज़िलों में छापेमारी अभियान चलाया, जो रियल-टाइम की निगरानी के माध्यम से समन्वित किये गए थे ताकि भागने से रोका जा सके।
- प्रभावः चार दिनों के भीतर 23 भगोड़े गिरफ्तार किये गए, लंबित वारंटों को लागू किया गया और धोखाधड़ी से प्राप्त सार्वजिनक धन की वसूली शुरू की गई।
 - आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने घोषणा की है कि 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक सभी आर्थिक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते।
- महत्त्वः यह अभियान उत्तर प्रदेश में वित्तीय अपराधों पर डिजिटल निगरानी और अंतर-जिला सहयोग के माध्यम से एक समन्वित राज्यव्यापी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है, जो आर्थिक न्याय की प्राप्ति में EOW के प्रयासों में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करता है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (Economic Offences Wing- EOW)

- 💎 परिचय:
 - 🍥 इसकी स्थापना **वर्ष 1970 में अपराध अन्वेषण विभाग (CID)** के अंतर्गत **आर्थिक अपराधों से निपटने** के लिये की गई थी।
 - वर्ष 1972 में सरकार ने EOW को 10 विभागों से संबंधित अपराधों की जाँच का दायित्व सौंपा- वन, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्थानीय निकाय, उद्योग, आबकारी/एक्साइज, कृषि, पंचायती राज, अल्प सिंचाई और बिक्री कर विभाग।
 - 1977 में EOW को पुनर्गठित कर इसे उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अलग विशेष अन्वेषण शाखा बनाई गई।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेस



IAS करेंट अफेयर्स





- 🏿 वर्ष 2006 में EOW के कार्यक्षेत्र को विस्तारित कर सभी सरकारी विभागों से जुड़े आर्थिक अपराधों को शामिल किया गया।
- वर्ष 2018 में सरकार ने इसके परिचालन क्षेत्र को सशक्त करने हेतु लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और कानपुर में चार EOW
 थाने स्थापित किये।
- प्रकार्य: यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं से जुड़े धोखाधड़ी, ठगी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों की जाँच करते हैं; अपराध की गंभीरता के आधार पर इसे निजी व्यक्तियों या संगठनों से संबंधित मामलों की जाँच का दायित्व भी सौंपा जा सकता है तथा यह सरकारी राजस्व हानि से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र कर उचित सरकारी कार्रवाई के लिये प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया संक्रमण की दर में गिरावट

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के **51 ज़िलों** के **782 प्रभावित ब्लॉकों में से 544 (लगभग 70%) ब्लॉकों** में फाइलेरिया संक्रमण की दर 1% से नीचे आ गई है। यह राज्य के फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में एक बड़ी उपलब्धि है।

शेष 238 ब्लॉकों में प्रयास जारी हैं। राज्य का लक्ष्य वर्ष 2027 तक फाइलेरिया का पूर्ण उन्मूलन करना है। इस दिशा में निगरानी को सुदृढ़ करने, अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ाने तथा ज़िलों के बीच फील्ड स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

फाइलेरियासिस से संबंधित प्रमुख तथ्य

- परिचयः फाइलेरियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो सूक्ष्म, धागे जैसे कृमियों/कीड़ों (फाइलेरिया) द्वारा होता है जिन्हें फाइलेरिया कहा जाता है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है और विश्व भर के उष्णकिटबंधीय तथा उपोष्णकिटबंधीय क्षेत्रों में लाखों लोगों को प्रभावित करता है।
- 💎 कारण एवं संक्रमण:
 - 🏿 लिंफैटिक फाइलेरियासिस एक परजीवी रोग है जो **फिलेरियोडिडिया परिवार** के **नेमाटोड्स (Roundworms**) से होता है।
 - इस रोग के लिये जिम्मेदार तीन मुख्य फाइलेरियल कृमि हैं:
 - ् **वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी:** यह 90% मामलों के लिये जिम्मेदार है,
 - ् **ब्रुगिया मैलेई:** यह शेष अधिकांश मामलों का कारण बनता है,
 - ् **ब्रुगिया टिमोरी:** यह भी इस रोग का कारण बनता है।
- 💎 लक्षणः लिंफैटिक फाइलेरियासिस संक्रमण में लक्षणहीन, तीव्र और दीर्घकालिक अवस्थाएँ शामिल होती हैं।
 - दीर्घकालिक अवस्था में, यह लिसका सूजन (lymphoedema) या हाथ-पाँव की सूजन/त्वचा एवं फीलपाँव या हाथीपाँव (Elephantiasis) और हाइड्रोसील (स्क्रोटल स्वेलिंग) का कारण बनता है।
- ▼ उपचार: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) लिंफैटिक फाइलेरियासिस के वैश्विक उन्मूलन को तीव्र करने हेतु तीन दवा वाले उपचार की अनुशंसा करता है। इसे ट्रिपल ड्रग थेरैपी (IDA) कहा जाता है, जिसमें आइवरमेक्टिन (Ivermectin), डाइएथिलकार्बामाज़ीन साइट्रेट (Diethylcarbamazine citrate) और अल्बेंडाज़ोल (Albendazole) का संयोजन शामिल होता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स









उत्तर प्रदेश में काऊ टूरिज़्म को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में "काऊ टूरज़्म''(गौ-पर्यटन) को विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें पर्यटक आकर्षण के रूप में बदलना है।

मुख्य बिंदु

💎 उद्देश्यः

- 🏿 **हर ज़िले में एक आदर्श गौशाला स्थापित करना:** इसे पर्यटन का मॉडल केंद्र और स्थानीय आय का स्रोत बनाया जाए।
- गौशालाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना: गोबर, मूत्र, दूध और घी जैसे गौ-आधारित उत्पादों के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देना। अधिकारियों को इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिये ज़िला-स्तरीय योजना तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं।
- महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHG) को शामिल करनाः स्थानीय स्तर पर गोबर आधारित और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों
 के निर्माण और विपणन में महिलाओं की भागीदारी बढाना।

💎 पहलः

- सरकार दीवाली अभियान शुरू करेगी, जिसमें गोबर से बने दीपक और सजावटी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा, तािक पर्यावरण-अनुकूल उत्सव मनाए जा सकें।
- ये उत्पाद 'aiaaल फॉर लोकल' (Vocal for Local) पहल के तहत प्रचारित किये जाएंगे, जिससे नागरिकों को सतत् और
 देशी उत्पाद अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

💎 प्रभावः

- गौशालाओं की आर्थिक क्षमता बढ़ाकर भटकते हुए पशुओं के प्रबंधन की चुनौती को हल करना।
- गौ-आधारित उद्योगों के माध्यम से रोज़गार और उद्यमिता के अवसर सृजित करना।
- गौ-रक्षा प्रयासों को सुदृढ़ करना और साथ ही पर्यावरण-सचेत पर्यटन तथा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना।

रक्षा मंत्री ने भविष्य हेतु तैयार सशस्त्र बलों पर पुस्तक क**ा विमोचन किया**

चर्चा में क्यों?

14 अक्तूबर, 2025 को **रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह** ने <mark>चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ</mark> जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक "*रेडी,* रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट II: शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोसी" का विमोचन किया।

मुख्य बिंदु

- 💎 यह पुस्तक भारत के सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों हेतु तैयार करने हेतु **एक व्यापक और दूरदर्शी रूपरेखा** प्रस्तुत करती है।
- इसमें युद्ध के बदलते स्वरूप का गहन विश्लेषण किया गया है, जिसमें संघर्ष के विकास का अवलोकन और उभरते क्षेत्रों, जैसे— साइबरस्पेस, अंतिरक्ष-संचालित अभियान तथा संज्ञानात्मक युद्ध (Cognitive Warfare) का अध्ययन शामिल है एवं इनकी भारतीय सशस्त्र बलों के लिये बढ़ती महत्ता को रेखांकित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेस



IAS करेंट अफेयर्स





सशक्त सैन्य नेतृत्व और संस्थागत अनुकुलनशीलता के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए लेखक भारत के सैन्य भविष्य की **साहसी पुनर्कल्पना** प्रस्तुत करते हैं, जो ऐतिहासिक ज्ञान से प्रेरित तकनीकी नवाचार का उपयोग करती है तथा सजग, विश्वसनीय और पुनरुत्थानशील भारत के दृष्टिकोण पर आधारित है।

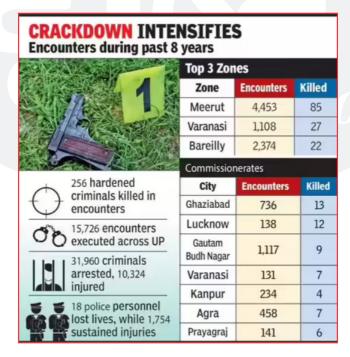
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद **वर्ष 2019** में स्थापित किया गया था। CDS **रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार** के रूप में सभी तीन सेनाओं (थ्री-सर्विसेज) से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- चीफ्स ऑफ स्टाफ किमटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में CDS को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के मुख्यालय द्वारा अपने निर्दिष्ट किये गए कार्यों को निभाने में सहायता प्रदान की जाती है।
- 💎 वेतन एवं रैंक: सैन्य कार्य विभाग (Department of Military Affairs) का प्रमुख होने के साथ ही CDS चार सितारा जनरल (Four-Star General) के पद पर होता है तथा उसका वेतन व भत्ते सेवा प्रमुख (Service Chief) के बराबर होते हैं।

उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर में 256 अपराधी ढेर

चर्चा में क्यों?

मिशन शक्ति 5.0 पहल के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों की धर-पकड़ की कार्रवाई तेज कर दी है। इस क्रम में पिछले 20 दिनों में <u>एनकाउंटर</u> में कई कुख्यात अपराधियों को या तो मारा गया या गिरफ्तार किया गया है।



रृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडे















मुख्य बिंद

- ▼ परिचय: मिशन शक्ति 5.0 का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा पुलिस में जनता का विश्वास दृढ़ करना है। यह सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति शून्य-सहनशीलता नीति को जारी रखता है।
- 💎 कानून और व्यवस्था का रिकॉर्ड (2017-25): वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश पुलिस ने 15,726 एनकाउंटर किये, जिनके परिणामस्वरूप:
 - 256 कुख्यात अपराधी मारे गए हुए
 - **७ 31,960 अपराधी गिरफ्तार** और 10,324 घायल हुए
 - 18 पुलिसकर्मी शहीद और 1,754 घायल हुए
- 💎 क्षेत्रवार आँकड़े (Zone-Wise Data):
 - मेरठ ज़ोन: 4,453 एनकाउंटर, 8,312 गिरफ्तारी, 85 मारे गए, 3,131 घायल (2 पुलिस शहीद, 461 घायल)
 - वाराणसी जोन: 1,108 एनकाउंटर, 2,128 गिरफ्तारी, 27 मारे गए, 688 घायल
 - आगरा ज़ोन: 2,374 एनकाउंटर, 5,631 गिरफ्तारी, 22 मारे गए, 816 घायल
 - लखनऊ ज़ोन: 846 एनकाउंटर, 17 अपराधी मारे गए
 - प्रयागराज जोनः 572 एनकाउंटर, 10 अपराधी मारे गए

💎 अतिरिक्त उपाय:

- गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और संपत्ति ज़ब्ती कानून का उपयोग संगठित अपराध सिंडिकेट्स के विरुद्ध किया गया।
- लगातार चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य आपराधिक नेटवर्क को तोड़ना और माफियाओं के वित्तीय संसाधनों को बाधित करना
 है।
- सरकार की रणनीति का मार्गदर्शन "एक अपराधी या तो कारावास में रहेगा या राज्य से बाहर" (A criminal will either be in jail or out of the state) सिद्धांत करता है।

💎 प्रभावः

- इस अभियान से अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई और राज्य में सुरक्षा की भावना को बल मिला।
- इसने जनता का कानून-व्यवस्था में विश्वास पुनर्स्थापित किया और उत्तर प्रदेश की सुरक्षित और भय-मुक्त राज्य की छवि को सुदृढ़ किया।

भारत में पुलिस एनकाउंटर से संबंधित दिशा-निर्देश

- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश (2014): पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (People's Union for Civil Liberties) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस एनकाउंटर में हुई मृत्यु में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने सभी एनकाउंटर मृत्यु के मामलों में FIR दर्ज करना और मिजिस्ट्रियल जाँच करवाना अनिवार्य किया,
 तािक कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित हो सके।
 - मृतक के निकटतम संबंधियों (Next of Kin) को जाँच प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिये, ताकि निष्पक्षता और
 पारदर्शिता बनी रहे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स





- 🍥 जाँच को स्वतंत्र एजेंसी जैसे कि अपराध अन्वेषण विभाग (CID) द्वारा किया जाना चाहिये, ताकि पक्षपात से बचा जा सके और हित संघर्ष (conflict of interest) रोका जा सके।
- NHRC दिशा-निर्देश (1997 और 2010):
 - वर्ष 1997: NHRC ने एनकाउंटर मृत्यु के मामलों के पंजीकरण, राज्य CID द्वारा स्वतंत्र जाँच और यदि पुलिस दोषी पाई गई तो निर्भर व्यक्तियों को मुआवज़ा प्रदान करने का निर्देश दिया।
 - वर्ष 2010 (संशोधन): एनकाउंटर मृत्यु की सूचना NHRC को 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य किया गया और तीन महीने के भीतर विस्तृत फॉलो-अप रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें पोस्टमार्टम, इनक्वेस्ट तथा जाँच निष्कर्ष शामिल हों।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024-25 में स्थापित हुई 4,000 नई फैक्ट्रियाँ

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश ने **औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति** की है एवं वर्ष 2024–25 के दौरान **4,000 नई फैक्ट्रियाँ** स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही, राज्य में संचालित फैक्ट्रियों की कुल संख्या 27,000 से अधिक हो गई है।

मुख्य बिंदु

- नवस्थापित औद्योगिक इकाइयाँ **इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा निर्माण, ऑटोमोबाइल, रसायन** तथा **नवीकरणीय ऊर्जा** जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करती हैं।
- औद्योगिक निवेश अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ जैसे पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों से आगे बढ़कर बरेली, कानपुर, झाँसी, गोरखपुर, आज़मगढ़ तथा प्रयागराज जैसे उभरते शहरों तक पहुँच रहा है।
- इन औद्योगिक इकाइयों में सिम्मिलित रूप से 12.8 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, जो भारत के कुल औद्योगिक कार्यबल का 8.3% है।
- वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, उत्तर प्रदेश अब भारत के शीर्ष 15 औद्योगिक राज्यों में चौथे स्थान पर पहुँच गया है।

इन्वेस्ट यूपी (Invest UP)

- 💎 परिचयः इन्वेस्ट यूपी, जिसे पहले उद्योग बंधु (Udyog Bandhu) के नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है।
 - 🍥 इसका उद्देश्य राज्य में **नए निवेश आकर्षित करना** तथा **मौजूदा और आने वाले उद्योगों की समस्याओं का समाधान** करना है।
- **मिशन:** राज्य की **निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी** के रूप में इन्वेस्ट यूपी का लक्ष्य **राज्य में तीव्र औद्योगिक** तथा **अवसंरचनात्मक** विकास हेतु नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से निवेश को आकर्षित करना है।
 - 💿 यह संगठन संभावित और मौजूदा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिये सलाहकार सेवाएँ (advisory services) प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख निवेश

इलेक्ट्रॉनिक्स: ₹3,700 करोड़ का HCL-फॉक्सकॉन OSAT निवेश राज्य की सेमीकंडक्टर (semiconductor) क्षेत्र में बडी उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है।

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













- टेक्सटाइल्स (वस्त्र उद्योग): उत्तर प्रदेश पीएम MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क और सिंथेटिक, डिफेंस एवं मेडिकल टेक्सटाइल्स पर केंद्रित मिनी पार्कों के माध्यम से अपनी वस्त्र मूल्य शृंखला (Textile Value Chain) को सुदृढ़ कर रहा है।
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV): EV नीति 2023 के तहत उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2028 तक 36 GWh बैटरी उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है।
- ▼ डिजिटल अवसंरचनाः नोएडा-ग्रेटर नोएडा भारत का प्रमुख डेटा सेंटर हब बनकर उभर रहा है, जहाँ एक एकीकृत एआई सिटी
 (Integrated AI City) विकसित करने की योजना है।

उत्तर प्रदेश बनाएगा डिजिटल कृषि नीति

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश कृषि वृद्धि एवं ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिक तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना (<u>UP-Agrees</u>) की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के अनुरूप एक डिजिटल कृषि नीति तैयार करें, ताकि एक सुरक्षित और सुदृढ़ साइबर अवसंरचना सुनिश्चित की जा सके।

"कृषि से उद्योग तक'' (From Agriculture to Industry) के दृष्टिकोण पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने मूल्य संवर्द्धन,
 प्रसंस्करण तथा सः्थानीय रोज़गार सृजन के महत्त्व पर भी प्रकाश डाला।

मुख्य बिंदु

- परिचयः प्रस्तावित डिजिटल कृषि प्रणाली के माध्यम से फसलों, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से संबंधित आँकड़ों तक रियल-टाइम एकीकृत पहुँच उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रणाली कृषि क्षेत्र में नवाचार-आधारित अनुसंधान तथा डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को प्रोत्साहित करेगी।
 - मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहयोग परियोजना (UP DASP) के समन्वय में इस पहल को कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) तथा किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के सहयोग से लागू किया जाए।
- UP DASP: यह 4,000 करोड़ रुपये (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की विश्व बैंक समर्थित परियोजना है, जिसे छह वर्षों की अविध में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के 28 ज़िलों में लागू किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य फोकस निम्नलिखित बिंदुओं पर है:
 - बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप संधारणीय कृषि वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
 - बाज़ार संपर्कों को सुदृढ़ करना और संसाधनों का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित करना।
 - उत्पादकता बढ़ाना तथा किष्ठि-आधारित उद्योगों के विकास को समर्थन देना।
- उत्पादकता संवर्द्धन पहलः उत्पादकता संवर्द्धन कार्यक्रम (Productivity Enhancement Programme) के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया जा रहा है:
 - भूमि विकास और जल संरक्षण।
 - मृदा स्वास्थ्य सुधार और आधुनिक प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि पद्धितयों को अपनाना।
 - लघु और सीमांत किसानों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण तथा विषणन सुविधाओं से जोड़ना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स





- वस्त क्लस्टर विकास: निम्नलिखित क्षेत्रों में क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं-
 - बुंदेलखंड में मूंगफली क्लस्टर।
 - वाराणसी में लाल मिर्च और सब्ज़ी क्लस्टर।
 - बराबंकी और आज़मगढ़ के बीच केले के क्लस्टर।
- मतस्य पालन क्षेत्र विकासः क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत निम्नलिखित व्यापक उपाय किये जा रहे हैं:
 - मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।
 - गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना और आधुनिक तकनीकों को अपनाना।
 - उत्पादन से लेकर विपणन तक प्रबंधन को सुदृढ़ करना।
 - परियोजना का उद्देश्य लगभग 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन हेतु विकसित करना है, जिससे करीब एक लाख परिवारों को लाभ पहुँचेगा।
- कृषि वित्त: मुख्यमंत्री ने कृषि वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें शामिल हैं:
 - लघु और सीमांत किसानों तथा कृषि-आधारित सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट सुविधाओं का विस्तार।
 - सुदृढ़ जोखिम-प्रबंधन तंत्र की स्थापना।
 - कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

उत्तर प्रदेश में पराली दहन पर अंकुश लगाने हेतु सब्सिडी योजना की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है, जिसके तहत <mark>पराली दहन (स्टबल बर्निंग)</mark> को रोकने में सहायता करने वाले कृषि उपकरणों पर 40-50% **सब्सिडी** दी जाएगी। यह कदम उत्तर भारत में **सिर्दियों के मौसम में <mark>वायू प्रदूषण</mark> के प्रमुख कारणों में से एक को कम करने के** उद्देश्य से उठाया गया है।

मुख्य बिंदु

- परिचय: यह सब्सिडी उन उपकरणों पर लागू होती है जैसे मल्चर्स और ट्रेडर्स, जो किसानों को फसल अवशेष को मृदा में मिलाकर इसे जैविक पदार्थ में परिवर्तित करने में सक्षम बनाते हैं, ताकि यह अपशिष्ट के बजाय उपयोगी बन सके।
- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण-मैत्री अवशेष प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना और फसल दहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है।
- कार्यान्वयन: किसान लाभ के लिये कृषि विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या निकटतम विभागीय कार्यालय जाकर आवेदन
- **टोकन भुगतान प्रणाली**: सरकार ने किसानों के लिये पारदर्शी और सुरक्षित आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये टोकन भुगतान प्रणाली भी शुरू की है।
 - ₹10,000 तक के उपकरणों के लिये कोई भुगतान नहीं।
 - ₹10,000 से ₹50,000 लागत वाले उपकरणों के लिये ₹2,500।
 - लाखों रुपये लागत वाले उपकरणों के लिये ₹5.000।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें















पराली दहन (स्टबल बर्निंग)

- पराली दहन एक ऐसी विधि है, जिसमें खेत से धान की फसल अवशेषों को हटाकर गेहूँ बोने के लिये तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया
 सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर तक होती है, जो दिक्षण-पश्चिम मानसून निर्वतन के समय घटित होती है।
- पराली दहन वह प्रक्रिया है जिसमें धान, गेहूँ जैसी फसलों की कटाई के बाद बचे हुए भूसे और अवशेषों को आग लगाकर नष्ट किया जाता है। यह आमतौर पर उन क्षेत्रों में आवश्यक होता है जहाँ संयुक्त फसल कटाई (combined harvesting) विधि अपनाई जाती है, जो फसल अवशेष पीछे छोड देती है।
- 💎 यह प्रथा उत्तर-पश्चिम भारत में अक्तूबर और नवंबर में सामान्य है, विशेषकर **पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदे**श में।

उत्तर प्रदेश में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने पाँच मेट्रो शहरों में **सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस** खोलने की घोषणा की है, ताकि भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से सीधे पूंजी निवेश आकर्षित किया जा सके और निवेशकों को राज्य के बढ़ते व्यापार अवसरों से जोड़ा जा सके।

मुख्य बिंदु

- 💎 **परिचयः** यह पहल **'इन्वेस्ट<u>यू.पी</u>.'** के तहत लागू की जाएगी, जो राज्य की निवेश संबर्द्धन और सुविधा एजेंसी है।
 - इसका उद्देश्य घरेलू पूंजी निवेश को उत्तर प्रदेश में लाना और राज्य के औद्योगिक तथा नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना
 है।
- 💎 सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस: मुंबई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली।
- स्टाफ संरचनाः प्रत्येक ऑफिस/कार्यालय में एक जनरल मैनेजर, एक अिसस्टेंट जनरल मैनेजर, दो उद्यमी मित्र, दो एकजीक्यूटिव और दो ऑफिस अिसस्टेंट होंगे।

महत्त्वः

- निवेशकों और राज्य सरकार के बीच की दूरी को समाप्त करने का लक्ष्य, रियल-टाइम संलग्नता तथा परियोजना सुविधा को आसान बनाना।
- 🍥 उत्तर प्रदेश की छवि को **निवेश-मैत्रीपूर्ण गंतव्य** के रूप में प्रबल करना और <mark>ईज़ ऑफ डूड़ंग बिज़नेस</mark> रैंकिंग में सुधार लाना।
- शहर के अनुसार फोकस क्षेत्र: प्रत्येक ऑफिस, संबंधित शहर की औद्योगिक क्षमता के अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करेगा:

शहर	फोकस सेक्टर्स
मुंबई	वित्तीय सेवाएँ, अवसंरचना, फिनटेक, ESG फंड्स
बंगलूरू	ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहन, डीपटेक
चेन्नई	ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग
हैदराबाद	फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी और उभरती तकनीकें
नई दिल्ली	इन्वेस्ट यू.पी. और एशिया-यूरोपीय संघ सुविधा कार्यालय

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से ज्डें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स



इष्टि लर्निंग



गढ़मुक्तेश्वर मेले का आयोजन मिनी कुंभ के रूप में

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के <mark>मुख्यमंत्री</mark> योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि **ऐतिहासिक <u>गढ़मुक्तेश्वर मेले</u> का आयोजन इस वर्ष 'मिनी कुंभ'** के रूप में किया ज**ा**एगा।

मुख्य बिंदु

- ▼ राज्य की गहरी आस्था, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक यह मेला 30 अक्तूबर से 5 नवंबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा तथा इसमें लगभग 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।
- 💎 **कार्तिक पूर्णिमा** पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्त्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है।
- गढ़मुक्तेश्वर का धार्मिक और पौराणिक महत्त्व बहुत अधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, महाभारत युद्ध के बाद, युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिये यहाँ गंगा में स्नान किया था।
- 💎 यह भी माना जाता है कि **भगवान परशुराम ने** इस स्थल पर पवित्र **मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की थी।**
- स्कंद पुराण और महाभारत में गढ़मुक्तेश्वर को एक पूजनीय तीर्थस्थल बताया गया है, जहाँ गंगा में स्नान करने तथा अपने पूर्वजों के लिये
 प्रार्थना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
- वार्षिक कार्तिक पूर्णिमा मेला न केवल राज्य की धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि इसकी जीवंत सांस्कृतिक एवं लोक परंपराओं को भी प्रतिबिंबित करता है, जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को बृजघाट और मुक्तेश्वर घाट पर आकर्षित करता है।

12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR 2.0 प्रारंभ

चर्चा में क्यों?

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है, जिसमें 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, जो 4 नवंबर, 2025 से शुरू होगा, अंतिम सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी एवं 1 जनवरी, 2026 को अर्हक तिथि निर्धारित की गई है।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्यः भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य त्रुटिरिहत मतदाता सूची तैयार करना है, तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र
 मतदाता छूटे नहीं तथा कोई भी अपात्र मतदाता शािमल न हो।
- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का क्रियान्वयनः SIR में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल होंगे।
 - इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का चयन उनके उच्च प्रतिशत वाले मतदाता सर्वेक्षण और पर्याप्त प्रशासिनक तैयारियों के कारण किया
 गया है, जिनमें प्रशिक्षित बी.एल.ओ., ज़िला मजिस्ट्रेट तथा ई.आर.ओ. शामिल हैं।
- महाराष्ट्र को इससे बाहर रखा गया है, क्योंिक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 31 जनवरी, 2026 तक स्थानीय चुनाव कराना अनिवार्य है।
- केरल को भी इससे बाहर रखा गया है, क्योंिक स्थानीय चुनावों पर चर्चा अभी भी चल रही है और अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयब कोर्म





- प्रक्रिया और सत्यापन मानकः देशव्यापी SIR के दौरान निवासियों को गणना के समय कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता
 नहीं होगी।
- नामांकन प्रपत्र में अब अंतिम SIR (2002-2004) से अभिभावक या परिजनों का विवरण दर्ज करने के लिये एक नया कॉलम शामिल किया गया है।
- जो मतदाता पहचान लिंक से वंचित रह जाएंगे, उन्हें पात्रता सिद्ध करने के लिये नोटिस जारी किये जाएंगे और इस प्रक्रिया में आधार केवल पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगा।
- लगभग 70-80% मतदाताओं के पूर्ववर्ती मतदाता सूची से डिजिटली जोड़ाव होने की संभावना है तथा प्रत्येक मतदाता को केवल एक हस्ताक्षरित प्रपत्र ही प्रस्तुत करना होगा।

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

- पिरचय: यह एक केंद्रित, समयबद्ध घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन प्रक्रिया है, जिसे मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (BLOs)
 द्वारा प्रमुख चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों को अद्यतन और सही करने हेतु संचालित किया जाता है।
 - यह प्रक्रिया नई प्रविष्टियों, विलोपन और संशोधन की अनुमित देकर मतदाता सूची को सटीक, समावेशी तथा त्रुटिरिहत
 बनाती है।
 - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने का अधिकार देती है, जिसमें किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराए जाने का प्रावधान है।
- SIR का संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मतदान का अधिकार है, जब तक कि उन्हें आपराधिक दोषसिद्धि, विकृत मस्तिष्क या भ्रष्टाचार के कारण कानून द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया जाए।
- ▼ पूर्व मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियाएँ: देश के विभिन्न भागों में 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रियाएँ आयोजित की गई थीं। बिहार में, पिछली मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया वर्ष 2003 में आयोजित की गई थीं।

उत्तर प्रदेश में 'लर्निंग बाय डूइंग' मॉडल

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 3,288 **सरकारी स्कूलों** तथा **ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIET)** में <mark>'लर्निंग बाय डूड़ंग</mark> (LBD)' <mark>मॉडल</mark> के माध्यम से अनुभवात्मक एवं कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक कार्य योजन**ा** विकसित की है।

मुख्य बिंदु

- 💎 मॉडल के बारे में:
 - इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, कौशल-संचालित और भविष्योन्मुखी बनाना है तथा रटने की पद्धित के स्थान पर "करके सीखने" की पद्धित अपनाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर





यह <u>राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020</u> के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो महत्त्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और नवाचार-संचालित शिक्षा पर ज़ोर देता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण:

- बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षण क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।
 - ्र यह प्रशिक्षण 66 आवासीय बैचों में आयोजित किया जाएगा. जिसमें कक्षा शिक्षण को प्रयोगों. परियोजनाओं. मॉडलों और वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- कक्षाओं को ऐसे स्थानों में परिवर्तित करना जो याद करने के बजाए **समझ, अन्वेषण और खोज** को प्रोत्साहित करें।
- शिक्षकों को व्यावहारिक शिक्षण विधियों से सुसज्जित करना जो छात्रों में रचनात्मकता, समस्या-समाधान और आलोचनात्मक सोच को बढावा दें।
- शिक्षार्थियों को कौशल-आधारित, नवाचार-संचालित और एआई-संचालित अर्थव्यवस्था के लिये तैयार करना।

- 🧑 लर्निंग बाय डूइंग' मॉडल बच्चों को स्वयं प्रयोग करने, प्रश्न पूछने और समाधान खोजने के अवसर देकर **सक्रिय अधिगम (Active** Learning) को प्रोत्साहित करता है।
- यह बच्चों में जिज्ञासा, विश्लेषणात्मक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति कौशल और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित करता है, जिससे विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता से सिक्रय शिक्षार्थी बन जाते हैं।
- इस पहल से उत्तर प्रदेश में **मूलभूत शिक्षा की पहचान पुनः परिभाषित** होने तथा अन्य राज्यों के लिये एक मानक स्थापित होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक्स हब

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा स्थित **बोडाकी** में **एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप तथा लॉजिस्टिक्स हब** के विकास को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो उत्तर भारत के सबसे उन्नत **मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स केंद्रों** में से होगा।

मुख्य बिंद्

- लॉजिस्टिक्स हब के बारे में:
 - 8,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली यह परियोजना 800 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी तथा इसमें कंटेनर टर्मिनल, वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीमॉडल परिवहन अवसंरचना शामिल होगी।
 - इन सभी का सीधा संबंध<u>डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)</u> से होगा। इसे <u>दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (DMIC)</u> तथा एकीकृत औद्योगिक टाउनिशप (IIT) अवसंरचना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।

उद्देश्य:

्दिल्ली-NCR, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे प्रमुख क्षेत्रों में **लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार** तथा **पारगमन समय** में कमी लाना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़े











- भारत क<u>ी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)</u> का समर्थन करना, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाना और माल प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है।
- यह पहल विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और वर्ष 2035 तक सात ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को समर्थन करती है।

अतिरिक्त अवसंरचनाः

 बोड़ाकी हब के अतिरिक्त, दादरी में 1,200 करोड़ रुपए की लागत से एक लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे ग्रेटर नोएडा भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक एवं औद्योगिक केंद्र बन सकेगा।

💎 प्रभाव:

- रोज़गार सृजनः यह लॉजिस्टिक्स हब हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उत्पन्न करेगा तथा लॉजिस्टिक्स प्रौद्योगिकी एवं गोदाम क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करेगा।
- औद्योगिक विकास: यह हब शीघ्र माल परिवहन को बढ़ावा देगा, जिससे औद्योगिक विकास को बल मिलेगा तथा मुख्य बंदरगाहों
 एवं औद्योगिक केंद्रों से संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा।

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक सुधार लागू

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक परिवेश में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें सामान्य व्यावसायिक अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिये अध्यादेश तथा <u>पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय</u> की स्थापना शामिल है।

मुख्य बिंदु

- 💎 व्यापार अपराधों का गैर-अपराधीकरण:
 - उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (व्यापार करने में सरलता) संशोधन अध्यादेश, 2025 पारित किया है, जो सामान्य व्यावसायिक अपराधों को अपराध मुक्त करने का प्रावधान करता है।
 - अब अवैध तालाबंदी, छँटनी और अपंजीकृत व्यवसाय चलाने जैसे उल्लंघनों के लिये कारावास के प्रावधानों को मौद्रिक जुर्माना तथा
 प्रशासनिक दंड से परिवर्तित दिया गया है।
 - अध्यादेश में कारखाना अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम और ठेका श्रम अधिनियम सहित 13 औद्योगिक एवं व्यावसायिक कानुनों में संशोधन किया गया है।
 - प्रशासनिक न्याय निर्णयन प्रक्रिया अब आपराधिक अदालती कार्यवाही का स्थान लेगी, जैसा कि गन्ना अधिनियम, 1953 में
 विवाद समाधान को सुव्यवस्थित करने के लिये देखा गया है।
 - ् ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की अनुमित देने वाले प्रावधान, जिनमें अब कारावास की सज्ञा नहीं होती, जैसे कि अग्नि निवारण और आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 के तहत, को प्रशासनिक दंड से परिवर्तित किया गया है।
 - 🧑 इस कदम से विनियामक भार में कमी, व्यापार में सुगमता तथा राज्य में निवेशकों का विश्वास बढ़ने की संभावना है।
- 💎 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय का गठनः
 - उत्तर प्रदेश ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की है, जो भारत में राज्य स्तर पर इस तरह का पहला निदेशालय है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स





- यह निदेशालय पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा और राज्य को पेरिस समझौत तथा COP28 परिणामों के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बनाने में मदद करेगा।
- इस पहल से उत्तर पुरदेश **जलवाय प्रशासन में सबसे सक्रिय राज्यों म**ें **से एक** बन गया है और यह वर्ष 2070 तक भारत के <mark>नेट</mark>-ज़ीरो उत्पर्जन लक्ष्य में योगदान देने का लक्ष्य रखता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना SAP में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

गन्ना किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिये गन्ने के राज्य परामर्शित मुल्य (SAP) में प्रति क्विंटल 30 रुपए की वृद्धि की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- सामान्य गन्ने के लिये SAP को 360 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबिक जल्दी पकने वाली किस्मों के लिये SAP अब 400 रुपए प्रति क्विंटल है, जो वर्ष 2017 के बाद से 30 रुपए की उच्चतम वृद्धि है।
- प्रभाव: गन्ने की कीमतों में वृद्धि से उत्तर प्रदेश के लगभग 46 लाख किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की संभवना है।
- इससे राज्य के **गन्ना कृषक समुदाय** को सहायता मिलेगी, जहाँ **गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.51 लाख** हेक्टेयर हो गया है।
- अन्य उपाय: राज्य सरकार ने बंद मिलों को पुनर्जीवित किया है, नई मिलें स्थापित की हैं तथा मौजूदा मिलों की पेराई क्षमता का विस्तार किया है, जिससे चीनी उत्पादन और <mark>इथेनॉल उत्पादन</mark> में वृद्धि हुई है।
- **दो चीनी मिलों में संपीडित बायोगैस (CBG**) संयंत्र भी स्थापित किये गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा को बढावा मिलेगा।
- स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली के तहत रकबा पंजीकरण, कैलेंडरिंग और पर्ची जारी करने जैसी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे **बिचौलियों को हटाकर किसानों को सीधे लाभ** मिल रहा है।

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडें









गना (Sugarcane):

- 💎 भौगोलिक स्थितियाँ:
 - 🧑 **तापमान:** 21-27°C के बीच, उष्ण और आर्द्र जलवायु।
 - वर्षा: लगभग 75-100 सेमी.
 - मृदा का प्रकार: गहरी, समृद्ध दोमट मृदा।
- 💎 शीर्ष उत्पादक राज्य:
 - उत्तर प्रदेश गन्ने का शीर्ष उत्पादक राज्य है लेकिन 122 सिक्रिय चीनी मिलों के साथ यह भारत में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान
 पर है।
- 💎 उचित एवं लाभकारी मुल्य (FRP):
 - यह चीनी मिलों द्वारा किसानों को दिया जाने वाले न्यूनतम मूल्य है।
 - इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
 की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
- 💎 राज्य परामर्शित मूल्य (SAP):
 - जबिक SAP केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकारें अपना स्वयं का SAP निर्धारित कर सकती हैं, जिसे चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान करना होगा यदि यह FRP से अधिक है।

लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश के **मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ** ने **लखनऊ** में प्रस्तावित **'नौसेना शौर्य संग्रहालय'** की तैयारियों की समीक्षा की। यह एक **महत्त्वाकांक्षी परियोजना** है, जो **हिंद महासागर क्षेत्र** में <mark>भारतीय नौसेना</mark> की वीरता, विरासत और तकनीकी कौशल का स्मरण कराएगी।

मुख्य बिंदु

- 💎 परिचय:
 - CG सिटी में एकाना स्टेडियम के पास विकसित किया जा रहा यह संग्रहालय उत्तर भारत का पहला समुद्री विरासत केंद्र होगा।
 - 🏿 इसका उद्देश्य शिक्षा, अनुभव और प्रौद्योगिकी को जोड़ते हुए **उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता** देना है।
 - यह संग्रहालय भारत की समुद्री शक्ति का उत्सव मनाने, राज्य की प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रीय गर्व को प्रेरित करने के लिये स्थापित किया जा रहा है।
- 💎 प्रारंभ और प्रगतिः
 - दिसंबर 2024 तक पूरा होने के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ 2022 में शुरू की गई इस परियोजना में लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण केवल 30% प्रगति हुई है और अब इसके वर्ष 2025 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेस



IAS करेंट अफेयर्स





परियोजना संरचनाः

- नौसेना शौर्य संग्रहालय को दो प्रमुख खंडों में विकसित किया जा रहा है:
 - ् INS गोमती शौर्य स्मारक (पवित्र स्मारक): इसमें INS गोमती (F-21), गोदावरी-क्लास की स्वदेशी मिसाइल फ्रिगेट शामिल है, जिसने भारतीय नौसेना में 34 वर्षों तक सेवा दी और <u>ऑपरेशन कैक्टस</u> तथा **ऑपरेशन पराक्रम** जैसी प्रमुख अभियानों में भाग लिया।
- **नौसेना शौर्य वाटिका:** इसमें **TU-142 समुद्री निगरानी विमान** (29 वर्षों की सेवा) और **सी किंग SK-42B हेलीकॉप्टर** शामिल होंगे, जो नौसैनिक अभियानों में उपयोग किये गए।

संरचना:

- संग्रहालय को नौसैनिक रेलिंग, पोर्टहोल शैली की खिड़िकयाँ और समुद्री प्रतीकों के साथ एक जहाज़ के अमूर्त रूप में तैयार किया गया है, जिसमें दो मुख्य क्षेत्र होंगे: व्याख्या केंद्र तथा ओपन-एयर संग्रहालय।
- प्रौद्योगिकी का विरासत से मिलन: संग्रहालय में आधुनिक प्रौद्योगिकी को ऐतिहासिक कहानियों के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:
 - इसमें इमर्सिव कहानी सुनाने के लिये 7D थिएटर होंगे।
 - विमान वाहक लैंडिंग और युद्धपोत सिमलेटर यथार्थवादी नौसैनिक अनुभव प्रदान करेंगे।
 - डिजिटल वाटर स्क्रीन शो और समुद्री जीवन एक्वेरियम भी होंगे।
 - भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिये जलमग्न द्वारका मॉडल बनाया गया है।
 - आगंतुक 'अपने नायकों की तरह पोशाक पहन सकते हैं' और आभासी नौसैनिक मिशन जैसी इंटरैक्टिव गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

पुरशासनिक निगरानी:

परियोजना की निगरानी के लिये **पर्यटन महानिदेशक की अध्यक्षता** में एक समिति बनाई गई है, जिसमें **मैरीटाइम हेरिटेज सोसायटी,** यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन और नौसैनिक विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

चर्चा में क्यों?

भारत में 2 अक्तूबर क<u>ो महात्मा गांधी</u> के जन्म दिवस के सम्मान में **गांधी जयंती** के रूप में मनाया जाता है।

इस दिन को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को 140 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था, जिससे इसे सार्वभौमिक महत्त्व प्राप्त हुआ।

मुख्य बिंदु

महात्मा गांधी के बारे में:

- 💎 जन्मः महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्तूबर, 1869 को पोरबंदर (गुजरात) में हुआ था।
- संक्षिप्त परिचयः वे एक प्रसिद्ध वकील, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्त्ता और लेखक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 💎 पुस्तकें: हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग (आत्मकथा)
- 💎 मृत्यु: 30 जनवरी, 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
 - 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का नेतृत्व: महात्मा गांधी 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बन
 गए और इन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिये अहिंसक प्रतिरोध तथा जन-आंदोलन की वकालत की।
 - वर्ष 1924 का बेलगाम अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी।
- असहयोग आंदोलन (NCM) (1920-22): गांधीजी ने जिलयाँवाला बाग हत्याकांड और दमनकारी रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया
 में NCM की शुरुआत की।
 - उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश संस्थाओं, वस्तुओं और सम्मानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया।
 - गांधीजी को बोअर युद्ध में उनकी भूमिका के लिये वर्ष 1915 में कैसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था लेकिन उन्होंने जिलयाँवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वर्ष 1920 में इसे वापस कर दिया था।
- दांडी मार्च (1930): गांधीजी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में गुजरात के तटीय शहर दांडी तक नमक मार्च का नेतृत्व किया। इस क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई।
- भारत छोड़ो आंदोलन (QIM), 1942: गांधीजी ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए QIM का आह्वान किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर







- उनके नारे "करो या मरो" ने लाखों लोगों को विरोध प्रदर्शनों, हडतालों और सविनय अवज्ञा के कार्यों में भाग लेने के लिये **प्रेरित किया,** जिससे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों की भागीदारी में तथा अधिक वृद्धि हुई।
- अहिंसा का दर्शन: अपने पूरे सिक्रयता अभियान के दौरान गांधीजी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर बल दिया तथा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की वकालत की।
 - उनके दृष्टिकोण ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित किया बल्कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जुनियर के नेतृत्व वाले विश्वव्यापी नागरिक अधिकार आंदोलनों को भी प्रेरित किया।

राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों?

आयुष मंत्रालय ने प्रो. बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंधन मूस ई.टी. और वैद्य भावना प्रशर को आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिये <u>राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार</u> 2025 से सम्मानित किया।

मुख्य बिंदु

- पुरस्कार के बारे में:
- यह पुरस्कार **आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित** किया गया है और पारंपरिक <u>भारतीय चिकित्सा</u> में **सर्वोच्च सम्मानों में से एक** माना जाता है।
- यह आयुर्वेद के प्रचार, संरक्षण और नवाचार में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।
- वर्ष 2025 के पुरस्कार विजेता आयुर्वेद के **तीन महत्त्वपूर्ण आयामों** का प्रतिनिधित्व करते हैं- **विद्वत्ता, पारंपरिक अभ्यास और वैज्ञानिक** नवाचार।
- विजेता:
 - प्रो. बनवारी लाल गौर आयुर्वेदिक शिक्षा और संस्कृत साहित्य में छह दशकों का योगदान देने वाले विद्वान तथा शिक्षाविद् हैं, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान सहित कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।
 - वैद्य नीलकंधन मूस ई.टी. केरल स्थित वैद्यरत्नम समूह के प्रमुख हैं और 200-वर्षीय आयुर्वेदिक परंपरा की आठवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - ्र उन्हें आयुर्वेद को जीवंत और समुदाय-उन्मुख अभ्यास के रूप में संरक्षित तथा आधुनिक बनाने के लिये जाना जाता है।
- वैद्य भावना प्रशर आयुर्जिनोमिक्स (Ayurgenomics) में अग्रणी हैं, जिन्होंने आयुर्वेदिक प्रकृति अवधारणाओं को आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान से जोड़ा और उनके **योगदान को राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कार्यक्रम** में एकीकृत किया गया।
- महत्त्व:
 - यह पुरस्कार पारंपरिक विद्वत्ता, पारंपरिक अभ्यास और आधुनिक विज्ञान के माध्यम से आयुर्वेद की निरंतरता तथा विकास को मान्यता देता है।
 - एकीकृत एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद की भूमिका को सुदृढ़ करता है।
 - पारंपरिक चिकित्सा और नवाचार में भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें















आयुष चिकित्सा पद्धति

आयुष में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी शामिल हैं, आयुर्वेद का 5000+ वर्षों का प्रलेखित इतिहास है।

भगवान ब्रह्मा को आयुर्वेद का

प्रथम प्रवर्तक

माना जाता है

आयुर्वेद

- (अ) **संहिता काल (१००० ईसा पूर्व):** परिपक्व चिकित्सा प्रणाली के रूप में उभरा
 - (h) चरक संहिता: सबसे प्राचीन और आधिकारिक संहिता
 - सुश्रुत संहिता: आठ विशिष्टताओं में मौलिक सिद्धांत और चिकित्सीय विधियाँ प्रदान करती है
- 🏵 मुख्य शाखाः
 - आत्रेय पुनर्वसु- चिकित्सकों की शाखा
 - दिवोदास धन्वतिर शल्यचिकित्सकों की शाखा

आयुर्वेद की शाखाएँ

- काय चिकित्सा-चिकित्सा।
- शल्य चिकित्सा- सर्जरी।
- शालाक्य तंत्र- ईएनटी और नेत्र विज्ञान।
- बाल रोग चिकित्सा।

- अगद तंत्र- विष विज्ञान।
- भूतविद्या मनोरोग।
- रसायन- कायाकल्प चिकित्सा और जराचिकित्सा।
- वाजीकरण तंत्र- सेक्सोलॉजी।

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा



प्राकृतिक चिकित्सा: 5 प्राकृतिक तत्वों - पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की सहायता से उपचार

- 🕞 शरीर की स्व-उपचार क्षमता सिद्धांतों और स्वस्थ जीवन के सिद्धांतों पर आधारित
- रोग-केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है

यूनानी

ग्रीस में अग्रणी, अरबों द्वारा ७ सिद्धांतों के रूप में विकसित (उमर-ए-तब्बिया)

- 🕟 बुकरात (हिप्पोक्रेटस) और जालीनुस (गैलेन) की शिक्षाओं के ढाँचे के आधार पर
 - 🕞 चार ह्यमर्स का हिप्पोक्रेटिक सिद्धांत अर्थात् रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त
- (S) WHO द्वारा मान्यता प्राप्त और भारत द्वारा वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में आधिकारिक दर्जा प्रदान किया गया

सिद्ध

१०००० - ४००० ईसा पूर्व; सिद्धर अगस्तियार- सिद्ध चिकित्सा के जनक

- निवारक, प्रोत्साहनात्मक, उपचारात्मक, पनर्जीवनात्मक और पुनर्वासात्मक स्वास्थ्य देखभाल
- 4 घटकः लैट्रो-रसायन विज्ञान, चिकित्सा अभ्यास, योग अभ्यास और बुद्धि
- अ ३ निदानात्मक ह्युमर्स (मुक्कुट्टरम) और ८ महत्त्वपूर्ण परीक्षणों (एन्वागई थेरवु) पर आधारित है

आयुर्वेद के 3 गुण (त्रिदोष): वात, पित्त और कफ

सोवा रिग्पा

उत्पत्ति: भगवान बुद्ध के समय २५०० वर्ष पूर्व भारत में

- 🕒 लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आदि के हिमालयी क्षेत्रों
- में पारंपरिक चिकित्सा। ﴿ भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनयम, 1970 (वर्ष 2010 में संशोधित) द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त।

होम्योपैथी

जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया

- 🕒 जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनिमैन ने इसके मूलभूत सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया।
- 🕒 औषधियाँ मुख्यतः प्राकृतिक पदार्थों (पौधे उत्पाद, खनिज, पशु स्रोत) से तैयार की जाती हैं।
- 🕟 वर्ष १८१० में यूरोपीय मिशनरियों द्वारा भारत में लाया गया; वर्ष १९४८ में आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई।
- 🕒 ३ प्रमुख सिद्धांत:
 - सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंट्रर ("सम: समम् शमयति" या "समरूपता")
 - सिंगल मेडिसिन
 - () मिनिमम डोज



Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडें

हिष् पतंजिल ने व्यवस्थित

रूप में योगसूत्र के रूप

में प्रतिपादित

किया

मेन्स टेस्ट सीरीज़













माई भारत मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने **माई भारत मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया,** जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से **यवाओं के नेतृत्व** और नागरिक सहभागिता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने **कॉमन सर्विस सेंटर (CSC**) को **माई भारत पोर्टल** से एकीकृत करने की भी घोषणा की, जिससे देश भर में युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की व्यापक पहुँच और गहन प्रसार सुनिश्चित हो सकेगा।

मुख्य बिंदु

💎 परिचय:

- यह एक ऑनलाइन युवा नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता मंच है, जिसे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्य विभाग (DoYA) के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य युवाओं को निर्बाध मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से स्वयंसेवा, इंटर्निशिप, मार्गदर्शन और सीखने के अवसर प्रदान करना है।
- यह वर्तमान में हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है तथा धीरे-धीरे इसमें अन्य भारतीय भाषाओं को भी जोडा जाएगा।

प्रमुख विशेषताएँ:

- सत्यापित अवसरः स्वयंसेवा, इंटर्निशिप, मेंटरशिप और अनुभवात्मक शिक्षा।
- डिजिटल मान्यताः बैज, प्रमाण-पत्र और व्यक्तिगत युवा प्रोफाइल।
- कॅरियर सशक्तीकरणः कौशल निर्माण संसाधन और एआई-सक्षम रिज्यूमे निर्माण।
- युवा अभियान: प्रमुख कार्यक्रमों और नागरिक पहलों में सिक्रय भागीदारी।
- इंटरैक्टिव लर्निंग: विकसित भारत युवा नेता संवाद (VBYLD) 2026 क्विज में भागीदारी।
- CSC के साथ एकीकरण: 5 लाख से अधिक ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) के विशाल नेटवर्क का लाभ लेते हुए अब माई भारत पोर्टल दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित होगा, जिससे युवाओं का निर्बाध पंजीकरण संभव होगा और VBYLD क्विज जैसी पहलों में उनकी भागीदारी संभव होगी।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्तूबर, 2023 को लॉन्च किया गया माई भारत प्लेटफॉर्म 1.81 करोड़ से अधिक युवाओं और 1.20 लाख संगठनों के साथ भारत के सबसे बड़े युवा-केंद्रित पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बन गया है, जो अमृत काल के दौरान युवाओं की सहभागिता, **नेतृत्व** तथा **राष्ट्र निर्माण** के लिये एक **डिजिटल आधार** के रूप में कार्य कर रहा है।

श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करते हुए युवाओं से उनकी निडर साहस और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का अनुकरण करने का आग्रह किया।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













मुख्य बिंदु

- वे एक भारतीय क्रांतिकारी, देशभक्त, वकील और पत्रकार थे, जिनका जन्म 4 अक्तूबर, 1857
 को मांडवी, गुजरात में हुआ था।
- लंदन में उन्होंने वर्ष 1905 में <u>इंडियन होम रूल सोसाइटी</u> की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित करना था।
- उन्होंने लंदन में भारतीय छात्रों के लिये छात्रावास और बैठक-स्थल के रूप में 'इंडिया हाउस' की स्थापना की।
- उन्होंने 'द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट' नामक पित्रका भी शुरू की, जिसका उद्देश्य युवा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रेरित करना था।
- 💎 वे <mark>बॉम्बे आर्य समाज</mark> के पहले **अध्यक्ष** थे और <mark>वीर सावरकर</mark> से प्रभावित थे।
- ब्रिटिश आलोचना के प्रत्युत्तर में वे इंग्लैंड से पेरिस चले गए और तत्पश्चात् प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान जिनेवा में स्थायी रूप से बस गए, जहाँ 30 मार्च, 1930 को उनका निधन को गया।
- उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी अस्थियाँ स्वतंत्र भारत में लाई जाएँ, यह इच्छा अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी की गई।
- 💎 उनकी स्मृति में 'क्रांति तीर्थ' नामक स्मारक का निर्माण मांडवी के निकट किया गया, जिसका उद्घाटन वर्ष 2010 में किया गया।

विश्व कपास दिवस 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पिबत्रा मार्गेरिटा ने 7 अक्तूबर को नई दिल्ली में विश्व कपास दिवस 2025 समारोह में भाग लिया।

यह कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय तथा भारतीय वस्त्र उद्योग पिरसंघ (CITI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसका विषय
 था— 'कपास 2040: प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धात्मकता'।

मुख्य बिंदु

- 💎 परिचय:
 - विश्व कपास दिवस की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी, जब उप-सहारा अफ्रीका के चार कपास उत्पादक देशों (बेनीन, बुर्किना फासो, चाड और माली), जिन्हें सामूहिक रूप से "कॉटन फोर'' (Cotton Four) कहा जाता है, ने 7 अक्तूबर को विश्व व्यापार संगठन (WTO) को यह दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था।

💎 उद्देश्य:

- इस दिवस का उद्देश्य अल्प विकिसत देशों के कपास और कपास से संबंधित उत्पादों के लिये वैश्विक बाज़ार तक पहुँच प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।
- साथ ही यह सतत् व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और विकासशील देशों को कपास मूल्य शृंखला के प्रत्येक चरण से अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेस



IAS करेंट अफेयर





💎 कपास से संबंधित तथ्यः

- शीर्ष पाँच कपास उत्पादक देश चीन, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान हैं, जिनकी कुल मिलाकर वैश्विक उत्पादन में तीन-चौथाई से अधिक हिस्सेदारी है।
 - ् भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल वैश्विक कपास उत्पादन का 23% है।
- 🏿 कपास से विश्व में लगभग **2.4 करोड़ उत्पादकों को आजीविका मिलती है तथा** 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलता है।
- कपास विश्व में पॉलिएस्टर के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला रेशा है, जो कुल रेशा मांग का लगभग 20%
 है।
- लगभग 80% कपास का उपयोग परिधानों में किया जाता है, शेष कपास का उपयोग घरेलू वस्त्रों और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है।

💎 भारत में नियंत्रण प्रणाली:

- भारतीय कपास निगम की स्थापना जुलाई 1970 में वस्त्र मंत्रालय के अधीन की गई थी।
- इसका उद्देश्य मृल्य समर्थन उपायों के माध्यम से कपास के मृल्य स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना है।
- इसके अतिरिक्त, यह निगम घरेलू वस्त्र उद्योग का व्यावसायिक खरीद परिचालन के माध्यम से समर्थन करता है, विशेष रूप से कम उत्पादन वाले मौसम के दौरान।

विश्व पर्यावास दिवस

चर्चा में क्यों?

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "संकट के लिये शहरी समाधान" विषय के साथ विश्व पर्यावास दिवस 2025 मनाया।

इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, प्रवासन और तीव्र शहरीकरण जैसी चुनौतियों से निपटने हेतु शहरों को अधिक लचीला, समावेशी तथा सतत् बनाने के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।

मुख्य बिंदु

💎 पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने अक्तूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में घोषित किया।
- 🍥 यह दिवस पहली बार वर्ष **1986 में** *"आश्रय मेरा अधिकार है"* **थी**म के साथ मनाया गया था और **नैरोबी** इसका मेज़बान शहर था।

💎 उद्देश्यः

 यह दिवस आवास की स्थिति पर विचार करने तथा सभी व्यक्तियों के लिये पर्याप्त आश्रय तक पहुँच के मौलिक अधिकार पर जोर देने के लिये मनाया जाता है।

💎 विषय 2025:

- 6 अक्तूबर को मनाए गए विश्व पर्यावास दिवस 2025 का विषय "शहरी संकट प्रतिक्रिया" था।
- यह जलवायु परिवर्तन और संघर्षी जैसी चुनौतियों से उत्पन्न शहरी असमानता को संबोधित करने तथा प्रभावी संकट प्रतिक्रिया
 उपकरणों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेस



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयल कोर्म





स्क्रॉल ऑफ ऑनर पुरस्कार

- संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावास कार्यक्रम (UN-Habitat) द्वारा वर्ष 1989 में शुरू किया गया स्क्रॉल ऑफ ऑनर अवार्ड मानव बस्तियों के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
- 💎 यह पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देता है:
 - आश्रय प्रावधानः पर्याप्त और सुलभ आवास।
 - निराश्रित लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालना।
 - संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण में नेतृत्व।
 - शहरी जीवन की गुणवत्ता और मानव बस्तियों में सुधार करना।

93वाँ वायुसेना दिवस

चर्चा में क्यों?

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने 93वें वायुसेना दिवस पर राष्ट्र को शुभकामनाएँ दीं और उन साहसी वायु सैनिकों को सम्मानित किया, जिन्होंने त्याग, समर्पण और कौशल के साथ देश की रकः्षा की।

मुख्य बिंदु

💎 परिचयः

- 🍥 यह दिवस 8 **अक्तूबर, 1932** को **भारतीय वायुसेना (IAF) की स्थापना** के सम्मान में प्रतिवर्ष 8 अक्तूबर को मनाया **जाता है।**
- भारतीय वायुसेना की पहली परिचालन उड़ान 1 अप्रैल, 1933 को हुई, जिसने दशकों से भारत की रक्षा को आकार देने वाली वायु शक्ति
 की नींव रखी।
- सीमित कार्मिक और विमानों वाली छोटी सेना से भारतीय वायुसेना अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन गई है, जो विभिन्न सैन्य और मानवीय मिशनों में सिक्रय है।
- 💎 आदर्श वाक्यः
 - भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य 'नभ: स्पर्श दीप्तम्'है, जो भगवद्गीता के ग्यारहवें अध्याय से लिया गया है।
- 💎 विषय:
 - इस वर्ष का विषय "
 <u>ऑपरेशन सिंद्र</u> में बल का योगदान" है।

💎 समारोहः

- इस वर्ष के समारोह में राफेल, Su-30MKI, C-17 ग्लोबमास्टर, अपाचे गार्जियन और अन्य विमानों के साथ भव्य फ्लाईपास्ट, साथ ही परेड, एयर शो तथा भारतीय वायुसेना की तकनीकी प्रगति एवं परिचालन तत्परता को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियाँ शामिल थीं, साथ ही प्रतिष्ठित मिग-21 को विदाई दी गई।
- यह परेड उत्तर प्रदेश के हिंडन एयर बेस पर आयोजित की गई।
- हेरिटेज फ्लाइट के भाग के रूप में पुनर्स्थापित हिंदुस्तान ट्रेनर-2 (HT-2) विमान, जो कि पहला स्वदेशी निर्मित भारतीय वायुसेना का विमान है, को भी पहली बार प्रदर्शित किया गया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर्स





पारंपरिक फ्लाईपास्ट और हवाई प्रदर्शन 9 नवंबर को गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष के वायुसेना दिवस समारोह का समापन होगा।

70वें फिल्मफेयर पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों?

70वें हंडई फिल्मफेयर पुरस्कार 2025, जो 11 अक्तूबर, 2025 को EKA एरेना, अहमदाबाद में गुजरात पर्यटन के सहयोग से आयोजित किये गए, हिंदी सिनेमा में उत्कृष्टता का एक विशिष्ट उत्सव था।

BEST ACTOR In a leading role (Male)

ABHISHEK BACHCHAN I WANT TO TALK



KARTIK AARYAN CHANDL







BEST ACTOR In a leading role (Female)

> ALIA BHATT **JIGRA**



BEST ACTRESS (CRITICS')

PRATIBHA RANTA LAAPATAA LADIES



BEST DIRECTOR KIRAN RAO LAAPATA



मुख्य बिंद्

- 💎 **परिचय:** यह समारोह **शाहरुख खान** और **करण जौहर** द्वारा होस्ट किया गया, जो 18 वर्षों के बाद फिल्मफेयर मंच पर फिर से मिले। यह आयोजन चमक-दमक और यादों का संगम था, जो सिनेमा की सात दशकों की उत्कृष्टता का उत्सव मनाने के लिये आयोजित किया गया।
- उद्देश्यः वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का उत्सव मनाना और कई श्रेणियों में उत्कृष्टता को सम्मानित करना।
- मुख्य जीत: 'लापता लेडीज़' ने रात की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, 13 ट्रॉफियाँ जीतीं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म (Best Film) शामिल है और इस तरह 'गली बॉय' (2019) का रिकॉर्ड बनाए रखा, जिसमें रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट थे।
 - 🍥 अभिनय श्रेणियों में अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये **सर्वश्लेष्ठ अभिनेता (परुष**) पुरस्कार साझा किया, जबकि आलिया भट्ट ने अपने शानदार रोल के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ट्रॉफी जीती।

टॉप इंडिविजुअल विनर्स		
नाम	पुरस्कार⁄अवार्ड्स	फिल्म ⁄ फिल्में
किरण राव	सर्वश्रेष्ठ निर्देशक	लापता लेडीज

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडें

मेन्स टेस्ट सीरीज़











शूजित सरकार	क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म	आई वांट टू टॉक
स्त्रेहा देसाई	बेस्ट स्क्रीनप्ले एंड बेस्ट डायलॉग	लापता लेडीज
राम संपथ	बेस्ट म्यूजिक एल्बम एंड बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर	लापता लेडीज
अचिंत ठक्कर	RD बर्मन अवार्ड (संगीत में उभरती प्रतिभा)	जिगरा, मिस्टर एंड मिसेज माही
ज़ीनत अमान, श्याम बेनेगल	लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड	भारतीय सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिये
(पोस्टह्यूमसली)		सम्मानित

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

चर्चा में क्यों?

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day) 2025 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने <u>राष्ट्रीय टेली-मेंटल हेल्थ कार्यक्रम (Tele-MANAS)</u> के तहत कई नई सुविधाओं की शुरुआत की।

मुख्य बिंद

- ऐप सुधार: Tele-MANAS मोबाइल ऐप उपयोगकर्त्ताओं को कहीं भी और कभी भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ किया जाता है।
 - 🦤 ऐप में अब **बहुभाषी इंटरफेस, चैटबोट, पहुँच सुधार** और **आपातकालीन प्रतिक्रिया मॉड्यूल** जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
 - ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं (असिमया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तिमल, तेलुगु, ओड़िया और पंजाबी) में उपलब्ध है,
 इसके अलावा अंग्रेज़ी तथा हिंदी में भी उपलब्ध है।
 - मुलभता सुविधाएँ इसे दिव्यांग व्यक्तियों, विशेषकर दृष्टिहीन लोगों के लिये उपयोगकर्त्ता-अनुकूल बनाती हैं।
 - चैटबोट "अस्मी'' (Asmi) उपयोगकर्त्ताओं को संवाद करने, जानकारी प्राप्त करने और मानिसक स्वास्थ्य सहायता तक पहुँचने की सुविधा देता है।
 - आपातकालीन मॉड्यूल संकट के समय त्विरत मार्गदर्शन और सहायता सुनिश्चित करता है।
- मेंटल हेल्थ एंबेसडर: मंत्री ने घोषणा की कि दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ एंबेसडर के रूप में नामित किया गया है, तािक मानिसक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
- 💎 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस:
 - परिचयः विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जिसे 10 अक्तूबर को मनाया जाता है, का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, संवाद को प्रोत्साहित करना और सभी के लिये मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुलभ बनाने के प्रयासों को सिक्रय करना है।
 - श्वीम: 2025 की थीम, "सेवाओं तक पहुँच- आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य'' (Access to Services Mental Health in Catastrophes and Emergencies), यह दर्शाती है कि प्राकृतिक आपदाओं, सशस्त्र संघर्षों और महामारी जैसी संकट की स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना कितना महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयल कोर्म





विश्व मानक दिवस

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने 14 अक्तूबर, 2025 को विश्व मानक दिवस (World Standards Day) कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

यह कार्यक्रम <u>भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)</u> द्वारा आयोजित किया गया था, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
 भारत सरकार के अंतर्गत आता है।

मुख्य बिंदु

- परिचयः राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (NITS) में आयोजित इस समारोह में भारत का राष्ट्रीय लाइटिंग कोड 2025 (National Lighting Code of India 2025) जारी किया गया, इसके साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) तथा ऑनलाइन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट (OSD) मॉड्यूल को भी BIS मानक पोर्टल पर लॉन्च किया गया।
- 💎 विश्व मानक दिवसः
 - परिचयः विश्व मानक दिवस पहली बार वर्ष 1970 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में मानकों (Standards) के महत्त्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था।
 - ्यह दिवस <mark>अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)</mark> ने **अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC)** और <mark>अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)</mark> के सहयोग से स्थापित किया था, ताकि वैश्विक स्तर पर मानक विकसित करने वाले समुदाय तथा उनके योगदान का सम्मान किया जा सके।
 - उद्देश्यः विश्व मानक दिवस उन मानकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका का उत्सव मनाता है, जो गुणवत्ता, सुरक्षा और सततता सुनिश्चित करते हैं। यह उन विशेषज्ञों-वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के सहयोगात्मक प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है, जो इन ढाँचों को बनाने के लिये कार्य करते हैं।
 - श्रीम: वर्ष 2025 की थीम, "A Shared Vision for a Better World: Standards for Sustainable Development Goals'' अर्थात् एक बेहतर विश्व के लिये साझा दृष्टि: सतत् विकास लक्ष्यों हेतु मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों की उस भूमिका पर जोर देती है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये वैश्विक सहयोग को बढावा देती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- BIS भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक संस्थान है, जिसे वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के समन्वित विकास के लिये BIS अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित किया गया।
 - 🧑 इसकी स्थापना प्रारंभ में **भारतीय मानक संस्था (ISI)** के रूप में हुई थी, जो **6 जनवरी, 1947** को अस्तित्व में आई।
- 💎 इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।
- BIS विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जैसे कि उत्पाद प्रमाणन (ISI मार्क), सोने और चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग, ईको मार्क योजना (पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लेबलिंग के लिये)।

<u>दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें</u>





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स



इष्टि लर्निंग



भारत-दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास (IN-RoKN)

चर्चा में क्यों?

भारत-दक्षिण कोरिया द्विपकृषीय नौसैनिक अभ्यास (IN-RoKN) का पहला संस्करण 13 अक्तूबर, 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नेवल बेस में शुरू हुआ, जो <mark>भारतीय नौसेना (IN)</mark> और कोरिया गणराज्य नौसेना (RoKN) के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदार*ी में एक* मील का पत्थर है।



मख्य बिंद

- परिचय: पहला IN-RoKN अभ्यास दो अलग-अलग चरणों- हार्बर फेज़ और सी फेज़ में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य दोनों समुद्री सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी), आपसी समझ तथा विश्वास को बढ़ाना है।
 - हार्बर फेज़: इस चरण में, दोनों देशों के नौसैनिक अधिकारी क्रॉस-डेक विजिट, पेशेवर अनुभवों का आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं का साझाकरण, खेलकृद गतिविधयों और क्रॉस-ट्रेनिंग सत्रों में शामिल होंगे। INS सह्याद्रि के कमांडिंग ऑफिसर भी वरिष्ठ RoKN अधिकारियों तथा स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों से शिष्टाचार करेंगे।
 - ज सी फेज़: समुद्री चरण में INS सह्याद्रि और ROKS Gyeongnam के बीच जटिल संयुक्त अभ्यास एवं संचालन संबंधी अभ्यास होंगे, जिनका उद्देश्य सामरिक समन्वय तथा परिचालन सहयोग को सुदृढ़ करना है।
- INS सह्याद्रि: INS सह्याद्रि एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित शिवालिक-क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे वर्ष 2012 में कमीशन किया गया तथा यह **ईस्टर्न नेवल कमांड के ईस्टर्न फ्लीट** के अधीन सेवाएँ प्रदान करता है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है।

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडें











- यह भारत की 'आत्मिनिर्भर भारत' (Self-Reliant India) पहल और उसकी स्वदेशी शिपिबिल्डिंग क्षमताओं का प्रतीक है।
- **रणनीतिक महत्त्व:** जैसे-जैसे <mark>इंडो-पैसिफिक क्षेत्र</mark> का भू-राजनीतिक महत्त्व बढ़ रहा है, भारत और कोरिया गणराज्य ने साझा हितों, **आपसी सम्मान तथा सामान्य मूल्यों पर आधारित सुदृढ़ समुद्री साझेदारी** विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता की दोबारा पुष्टि की है।

विश्व खाद्य दिवस 2025

चर्चा में क्यों?

विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्तूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और संधारणीय कृषि के संबंध में जागरूकता बढाना है।

मुख्य बिंद्

- परिचयः विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा 16 अक्तूबर, 1945 को स्थापित खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है।
 - ⊚ विश्व खाद्य दिवस 1979 में FAO की 20वीं महासभा के दौरान अस्तित्व में आया और 1984 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकृति प्रदान की।
 - 🍥 भोजन का अधिकार 1948 के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- थीम: वर्ष 2025 के लिये थीम है "बेहतर भोजन और बेहतर भिवष्य साथ-साथ", जो एग्रीफूड सिस्टम को बदलने में वैश्विक सहयोग की शक्ति को उजागर करती है।
- **भारत की स्थिति:** पिछले दशक में भारत का अन्न उत्पादन लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा है, जो दढ़ कृषि विकास को दर्शाता है।
 - फल और सब्जियों का उत्पादन भी महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा है तथा इसी अवधि में यह 64 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक हो गया।
 - **भारत** अब दुध और बाजरे (मिलेट्स) के उत्पादन में विश्व में **प्रथम स्थान** पर है, जबकि मछली, फल तथा सिब्ज़ियों के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। वर्ष 2014 के बाद से शहद एवं अंडे का उत्पादन दोगुना हो गया है।
- भारत की पहलें: राष्ट्रीय खाद्य सरक्षा अधिनियम, 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम पोषण (POSHAN) <u>योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राइस फोर्टफिकेशन</u> और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (PSF) जैसी प्रमुख पहलें भारत की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रही हैं।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दल कलाम की जयंती

चर्चा में क्यों?

15 अक्तूबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें पृष्पांजलि अर्पित की।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडें

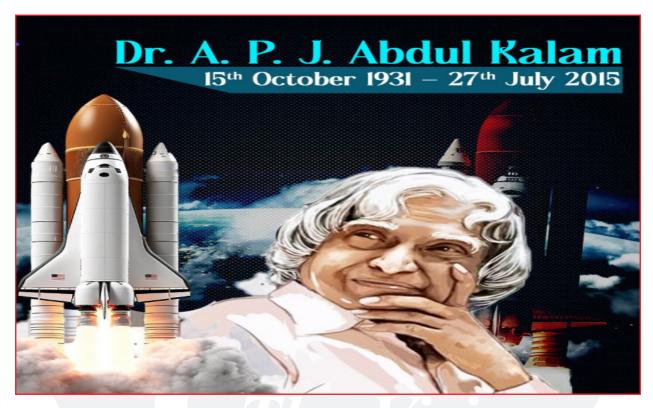












मुख्य बिंद

- 💎 परिचयः डॉ. अवुल पाकिर जैनुलआबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्तूबर, 1931 को तिमलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त की थी।
- अंतरिक्ष अनुसंधान: वे भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV-III) के परियोजना निदेशक रहे, जिसने जुलाई, 1980 में **रोहिणी उपग्रह** को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिससे भारत विशिष्ट "स्पेस क्लब" का सदस्य बना।
 - उन्होंने इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से **PSLV कॉन्फिगरेशन** के निर्माण में, जो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं की आधारशिला बन गया।
- रक्षा विकासः एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, उन्होंने AGNI और PRITHVI जैसी प्रमुख मिसाइल प्रणालियों के विकास तथा संचालन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 - जुलाई, 1992 से दिसंबर, 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DRDO) के सचिव के रूप में, डॉ. कलाम ने भारत के मिसाइल प्रणालियों के सशस्त्रीकरण का नेतृत्व किया तथा सफल <mark>पोखरण-II परमाण</mark> परीक्षणों की देख-रेख की, जिससे भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र बना।

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

मेन्स टेस्ट सीरीज़











- 🍥 उनका योगदान रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता तक विस्तृत था, जिसमें <mark>लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट (LCA</mark>) के विकास में उनकी अहम भूमिका शामिल है।
- विकसित भारत का दृष्टिकोण: उनका नेतृत्व टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल (TIFAC) तक विस्तृत था, जहाँ उन्होंने अध्यक्ष के रूप में **टेक्नोलॉजी विज़न 2020** परियोजना का नेतृत्व किया।
- पुस्तकें: उनकी रचनाएँ जैसे- "विंग्स ऑफ फायर", "इंडिया 2020 ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम", "माय जर्नी"और "इग्नाइटेड माइंड्स - अनलीशिंग द पावर विदिन इंडिया"- अनेक भाषाओं में अनुदित की गई हैं, जो आज भी विश्वभर में लोकप्रिय हैं।
- सम्मान और परस्कार: उन्हें 30 मानद डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त हुईं तथा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों जैसे- पदम भूषण (1981), पदम विभूषण (1990) और भारत रल (1997) से सम्मानित किया गया।
 - **भारत के राष्ट्रपति:** 25 जुलाई, 2002 को डॉ. कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जहाँ उन्होंने विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। उनकी राष्ट्रपति अवधि का प्रमुख लक्ष्य था- भारत को वर्ष 2020 तक एक वैश्विक नेता के रूप में परिवर्तित करना। उन्होंने वैज्ञानिक उत्कृष्टता, राष्ट्रीय गौरव और युवा सशक्तीकरण की एक अमिट विरासत स्थापित की।

विशाखापत्तनम में गुगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब

चर्चा में क्यों?

गुगल ने आंध्र प्रदेश के **विशाखापत्तनम** में अत्याधिनक **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI**) हब स्थापित करने के लिये वर्ष 2026 से 2030 तक अगले पाँच वर्षों में 15 अरब डॉलर निवेश करने की योजना की घोषणा की है।

मुख्य बिंद

- परिचयः इस परियोजना की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित 'भारत AI शक्ति' कार्यक्रम के दौरान की गई, जहाँ **ग**ृगल के CEO सुंदर **पिचाई** ने बताया कि उन्होंने इस परियोजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की थी।
- सबसे बड़ा AI हब: विशाखापत्तनम में बनने वाला नया डेटा सेंटर अमेरिका के बाहर गुगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब होगा।
 - यह पहल गूगल की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कंपनी इस वर्ष लगभग 85 अरब डॉलर का निवेश करके अपने डेटा सेंटर नेटवर्क का विस्तार कर रही है, ताकि विश्वभर में बढ़ती ${
 m AI}$ सेवाओं की मांग को पूरा किया जा सके।
- सेवाएँ: गूगल AI हब पूरी तरह से AI समाधान प्रदान करेगा, जिसमें गूगल के स्वामित्व वाले <mark>टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स (TPU)</mark> का उपयोग किया जाएगा, जो पारंपरिक चिप्स की तुलना में दोगुनी ऊर्जा-कुशल हैं।
 - यह हब डेटा को स्थानीय रूप से संग्रहित करेगा ताकि भारत की **सॉवरेन AI आवश्यकताओं** का पालन हो सके, स**ाथ** ही गुगल के उन्नत AI मॉडल जैसे- जेमिनी (Gemini), इमैजिन (Imagine) और वीओ (Veo) को भी तैनात किया जाएगा।
- **सहयोग:** इस महत्त्वाकांक्षी पहल का समर्थन करने के लिये **अडानी समह** और **एयरटेल** ने गुगल के साथ साझेदारी की है। इसके अंतर्गत आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक न्यू इंटरनेशनल सबसिया गेटवे भी शामिल है।

समुद्र शक्ति का पाँचवाँ संस्करण

चर्चा में क्यों?

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें











भारतीय नौसेना 14 से 17 अक्तूबर तक **आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम** में इंडोनेशियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास **'समुद्र** शक्ति' के पाँचवें संस्करण की मेजबानी कर रही है।



मुख्य बिंदु

- परिचयः इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य समुद्र और तट दोनों पर पेशेवर तथा परिचालनिक गतिविधियों की एक शृंखला के माध्यम से दोनों देशों के बीच अंतरसंचालन क्षमता (interoperability) को बढ़ाना तथा समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना है।
- 💎 भाग लेने वाली इकाइयाँ:
 - INS कवरत्तीः भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की एक पनडुब्बी-रोधी युद्धक (Anti-Submarine Warfare) कॉर्वेट।
 - KRI जॉन ली: इंडोनेशियाई नौसेना की एक कॉर्वेट, जो एक एकीकृत हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है।
- हार्बर फेज़: हार्बर चरण में गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे- क्रॉस-डेक दौरे, संयुक्त योग सत्र, मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज (SMEE) कार्यक्रम के तहत पेशेवर आदान-प्रदान, जो दोनों देशों के नौसैनिक किमियों के बीच पेशेवर संवाद तथा सौहार्द बढाने के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं।
- सी चरण: सी चरण में जटिल और उच्च-गितशीलता वाले समुद्री अभियान होंगे, जिनका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच टैक्टिकल समन्वय (tactical coordination) में सुधार करना है। इन अभियानों में हेलीकॉप्टर युद्धाभ्यास, हवाई रक्षा अभ्यास (Air Defence Exercises), हथियार फायरिंग ड्रिल्स और विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सिजर (VBSS) ऑपरेशन्स शामिल होंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स





- **महत्त्व:** यह अभ्यास **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने** के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
- भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य सैन्य अभ्यास: गरुड शक्ति, IND-INDO CORPAT

संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्त्ता देशों के (UNTCC) प्रमुखों का सम्मेलन 2025

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्त्ता देशों के (UNTCC) प्रमुखों का सम्मेलन 2025, जिसे भारतीय सेना ने 14 से 16 अक्तूबर, 2025 तक आयोजित किया, में 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेताओं को एकत्रित किया गया, जो वैश्विक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



मुख्य बिंदु

- परिचय: इस सम्मेलन में 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं, जिनमें अल्जीरिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, फ्राँस, घाना, भारत, इटली, केन्या, मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, पोलैंड, रवांडा, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, उरुग्वे और वियतनाम शामिल हैं।
 - 🍥 इस कार्यक्रम में रक्षा प्रदर्शनियाँ भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शांति स्थापना अभियानों के लिये साझा क्षमताओं का निर्माण करना है।
- **उद्देश्य:** UNTCC एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य परिचालनिक चुनौतियों, विकसित हो रहे खतरों, अंतर-संचालन क्षमता, निर्णय-निर्माण में समावेशिता और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को सुदृढ़ करने में प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण की भूमिका पर चर्चा करना है।
 - भारत, जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्त्ताओं में से एक है, ने **भविष्य के शांति स्थापना अभियानों के लिये**

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा, ज्ञान साझा करने और आपसी समझ विकसित करने के उद्देश्य से इस उच्च स्तरीय मंच का आयोजन किया है।

- **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन:** प्रमुखों ने भारतीय सेना द्वारा एकीकृत, <u>आधिनक सैन्य प्रौद्योगिकी</u> का प्रदर्शन देखा, जिसमें विभिन्न स्वदेशी सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिये 4C सूत्र: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शांति स्थापना में उभरती चुनौतियों का समाधान करने हेतु *परामर्श* (Consultation), सहयोग (Cooperation), समन्वय (Coordination) और क्षमता निर्माण (Capacity Building) के मार्गदर्शक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसे 4C सूत्र कहा गया।
 - उन्होंने यह भी बताया कि **नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर UN पीसकीपिंग** ने 90 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है, जिससे शांति सैनिकों के बीच अंतरसंचालन क्षमता (Interoperability) के विकास में महत्त्वपर्ूण योगदान मिला है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNPK)

- 💎 पहला UNPK मिशन, **संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO**), मई 1948 में स्थापित किया गया था ताकि इजरायल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच **आर्मिस्टिस समझौते** की निगरानी एक छोटे सैन्य पर्यवेक्षक दल के माध्यम से की जा सके।
- ं उन्हें <mark>संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद</mark> द्वारा **युद्धविराम और शांति समझौतों का समर्थन करने** के लिये तैनात किया जाता है तथा इन्हें **ब्लू** हेलमेट्स कहा जाता है क्योंकि हल्का नीला रंग UN ध्वज पर शांति का प्रतीक है।
- वर्तमान में, 119 देशों के 61,000 से अधिक सैन्य और पुलिस शांति सैनिक तथा 7,000 से अधिक नागरिक कर्मी 11 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।

पिंकी आनंद बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों?

डॉ. पिंकी आनंद, वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत की पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, को बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (BICC) में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि वर्ष 2024 में पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल की उसी न्यायालय में नियुक्ति के बाद हुआ है।

डॉ. पिंकी आनंद

- पृष्ठभूमि: हार्वर्ड लॉ स्कूल की स्नातक और इन्लैक्स स्कॉलर, डॉ. पिंकी आनंद के पास 40 वर्षों से अधिक का विधिक अनुभव है। उन्होंने भारत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (2014-2020) के रूप में कार्य किया और उन्हें संवैधानिक कानून, सिविल मध्यस्थता तथा आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व: उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय **मंचों** पर किया है, जिनमें **ब्रिक्स (BRICS)** शामिल हैं; **ब्रिक्स लीगल फोरम** की संस्थापक सदस्य भी हैं।
- **सम्मान:** उन्हें फ्राँस के राष्ट्रपति द्वारा **फ्रेंच नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट** से सम्मानित किया गया।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें











बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (BICC)

- बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (Bahrain International Commercial Court- BICC) की स्थापना जटिल सीमा पार वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिये की गई है। यह न्यायालय 5 नवंबर, 2025 को न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ अपना कार्य आरंभ करेगा, जिसमें बहरीन के राजपरिवार और प्रधानमंत्री की उपस्थिति होगी।
- BICC की अध्यक्षता प्रसिद्ध मध्यस्थता विशेषज्ञ **जान पॉल्सन** कर रहे हैं और इसमें 17 न्यायाधीश शामिल हैं- जिनमें 7 महिलाएँ एवं 10 पुरुष हैं, जो विश्व के विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- यह न्यायालय मार्च, 2024 में **बहरीन और सिंगापुर के बीच हुई एक संधि** के तहत स्थापित किया गया है तथा इसका ढाँचा **सिंगापुर** अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (Singapore International Commercial Court- SICC) के मॉडल पर आधारित है ताकि वाणिज्यिक विवाद समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।

नीरज चोपड़ा को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि

चर्चा में क्यों?

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को राष्ट्र के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के सम्मान में प्रादेशिक सेना (Territorial Army) में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है।

पिपिंग समारोह नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित किया गया, जहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी की उपस्थिति में औपचारिक रूप से यह रैंक प्रतीक /चिह्न (Rank Insignia) प्रदान किया।



'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













मुख्य बिंदु

▼ परिचयः 24 दिसंबर, 1997 को हिरयाणा के पानीपत जिले के खंडरा गाँव में जन्मे नीरज चोपड़ा एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और भारत के सबसे प्रतिष्ठित खिलाडियों में से एक बन चुके हैं।

भारतीय सेना में यात्राः

- नीरज चोपड़ा अगस्त, 2016 में भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में नायब सूबेदार (Naib Subedar) के रूप में शामिल हुए थे तथा वर्ष 2021 में उन्हें एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलिब्धियों के लिये सूबेदार (Subedar) के पद पर पदोन्नत किया गया।
- वर्ष 2022 में, ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें सूबेदार मेजर (Subedar Major) पद पर पदोन्नत किया गया और भारतीय सेना के सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान 'परम विशिष्ट सेवा पदक' से सम्मानित किया गया।
- अप्रैल, 2025 में, राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रसेवा और उत्कृष्ट खेल उपलिब्धियों की मान्यता में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल खेल् मैं भिक्राका विकास tenant Colonel) की उपाधि प्रदान की।
- टोक्यो ओलंपिक 2020: ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा।
- 🌀 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023: स्वर्ण पदक जीता, जिससे वैश्विक एथलेटिक्स में भारत की उपस्थिति और दृढ़ हुई।
- पेरिस ओलंपिक 2024: रजत पदक प्राप्त किया, जिससे उनका निरंतर उच्च प्रदर्शन स्तर बना रहा।
- एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल: कई स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक स्पर्द्धा में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की।
- डायमंड लीग एवं अन्य प्रतियोगिताएँ: लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त िकया तथा वर्ष 2025 में 90.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो
 (Personal Best Throw) कर भारतीय एथलेटिक्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया।

पुरस्कार एवं सम्मानः

- विशिष्ट सेवा पदक (2023)
- परम विशिष्ट सेवा पदक (2022)
- णद्मश्री (2022)
- मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (2021)
- अर्जुन पुरस्कार (2018)

अंतर्राष्ट्रीय स्नो लेपर्ड दिवस और '#23for23' पहल

चर्चा में क्यों?

भारत ने 23 अक्तूबर, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्त्रो लेपर्ड दिवस मनाया, जिसमें '#23for23' शीर्षक के तहत एक विशिष्ट राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। इस अभियान ने लोगों को 23 मिनट शारीरिक गतिविधि के लिये समर्पित करने हेतु प्रेरित किया, ताकि स्त्रो लेपर्ड (हिम तेंदुए) और उनके संवेदनशील उच्च ऊँचाई वाले आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

मुख्य बिंदु

- ▼ परिचय: '#23for23' अभियान को वर्ष 2023 के लिये 23 मिनट की सिक्रय भागीदारी का प्रतीक बनाकर शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण में जागरूकता और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।
 - यह अभियान ग्लोबल स्त्रो लेपर्ड और ईकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP) के अंतर्गत, तथा स्त्रो लेपर्ड ट्रस्ट वर्ल्डवाइड

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयब कोर्स





के सहयोग से आयोजित किया गया।

- भारत की संरक्षण उपलब्धियाँ:
 - भारतीय हिमालय में की गई पहली स्त्रो लेपर्ड गणना में 718 स्त्रो लेपर्ड पाए गए, जिनमें से 477 लहाख में हैं।
 - भारत ने उच्च ऊँचाई पर स्थित हिमालयों के लिये स्नो लेपर्ड को एक फ्लैगिशिप (मुख्य) प्रजाति के रूप में चिह्नित किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्त्रो लेपर्ड दिवस: यह दिवस वर्ष 2013 में स्थापित हुआ, जब किर्गिजस्तान में विशक्तिक घोषणा को अपनाने के बाद उन 12 देशों ने, जिनमें स्नो लेपर्ड की आबादी है, संरक्षण प्रयासों में सहयोग करने पर सहमित व्यक्त की।
- स्त्रो लेपर्ड की मेज़बानी करने वाले देश: अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें















💎 परिचयः मध्यम आकार की बिल्लियाँ जो अपनी चतुराई के लिये जानी जाती हैं और कठोर, ऊँचाई वाले वातावरण में जीवित रहने की क्षमता रखती हैं।

हिम तेंदुआ (Snow Leopard)



प्राय: इसे "Ghost of the Mountains" अर्थात "पहाड़ों का भूत" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

आवास

मध्य और दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र हिम तेंदुआ रेंज वाले देशों की संख्या (12) - भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान

🗣 भारत में

पश्चिमी हिमालय : जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश पूर्वी हिमालय : उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश

खतरे

- मानव- हिम तेंदुआ संघर्ष
- शिकार एवं आवास की क्षति
- अवैध शिकार
- जलवायु परिवर्तन

प्रमुख स्थान 📍

हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख (इसे हिम तेंदुओं की 'वैश्विक राजधानी' के रूप में भी जाना जाता है) ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम

संरक्षण स्थिति 🖣

IUCN रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable) CITES - परिशिष्ट - I भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची 1

संरक्षण हेतु प्रयास

- ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) कार्यक्रम
- हिमाल संरक्षक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम
- प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (PSL)
- हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पश्चिम बंगाल

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडें

मेन्स टेस्ट सीरीज़









- - 💎 पर्यावास: मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ों में मूल निवासी, आमतौर पर 9,800 से 17,000 फीट की ऊँचाई पर पाई जाते हैं।
 - वन्य में लगभग 3,500 से 7,000 स्त्रो लेपर्ड होने का अनुमान लगाया गया है।
 - विशेषताएँ: मोटे, धुसर-सफेद फर से युक्त, जो बर्फ और चट्टानों के बीच छिपने में सहायता करता है।
 - पारिस्थितिक महत्त्व: ये शीर्ष शिकारी तथा संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति उच्च ऊँचाई पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाती है।
 - इनके शिकार से गिद्ध और भेडिये जैसे अपशिष्ट का सेवन करने वाले जीवों को भोजन मिलता है, जिससे अन्य प्रजातियों का समर्थन होता है।

वैश्विक वन संसाधन मृल्यांकन 2025

चर्चा में क्यों?

भारत ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA) 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में नीवें स्थान पर पहुँचकर पर्यावरण संरक्षण में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा बाली, इंडोनेशिया में जारी की गई है।

यह पूर्व में हुए मूल्यांकन में **दसवें स्थान** से सुधार को दर्शाता है और देश के सतत् वन प्रबंधन के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

मुख्य बिंदु

- परिचय: वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (FRA), जिसे FAO द्वारा संचालित किया जाता है, विश्व के वन संसाधनों का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें उनकी स्थिति, प्रबंधन और उपयोग शामिल हैं। यह **देशों द्वारा प्रस्तुत डेटा** पर आधारित होता है, जिसे विशेषज्ञ समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।
 - यह रिपोर्ट सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा, पेरिस जलवाय समझौता, कुनिमंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचा और संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2017-2030 के लिये वन रणनीतिक योजना जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की निगरानी में सहायता करती है।

भारत के संबंध में निष्कर्ष:

- िरपोर्ट में बताया गया है कि भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 72.73 मिलियन हेक्टेयर है, जिससे देश विश्व में नौवें स्थान पर है।
- वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत अभी भी दुनिया में **तीसरे स्थान** पर है, जो उसके बड़े पैमाने पर वनीकरण और संरक्षण पहलों की सफलता को दर्शाता है।
- FAO रिपोर्ट में भारत के **कुषि-वानिकी (एग्रोफॉरेस्टी) क्षेत्र** को भी उजागर किया गया है। 91 देशों में 55.4 मिलियन हेक्टेयर एग्रोफॉरेस्ट्री भूमि में भारत और इंडोनेशिया मिलकर लगभग 70% वैश्विक कुल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
 - ् केवल भारत में 12.87 मिलियन हेक्टेयर भूमि एग्रोफॉरेस्ट्री में है, जो कार्बन संग्रहण, आजीविका सृजन और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वैश्विक रुझानः

FRA 2025 के अनुसार, वर्तमान में विश्व के वन लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत हैं, जो पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई है।

टिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













- रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर **वनोन्मुलन** (**वनों की कटाई) की दर में कमी** देखी गई है, हालाँकि वर्तमान दर **प्रतिवर्ष 10.9 मिलियन** हेक्टेयर अभी भी अधिक है।
- अब विश्व के आधे से अधिक जंगल **दीर्घकालिक प्रबंधन योजनाओं** के तहत हैं और लगभग 20**% वन कानूनी रूप से स्थापित संरक्षित** क्षेत्रों में आते हैं।
- वैश्विक स्तर पर रूस सबसे ऊपर है, जिसका वन क्ष**ेत्र 832.6 मिलियन हेक्टेयर** है, इसके बाद **ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका और चीन** का स्थान है।

पूर्वी तिमोर आसियान का 11वाँ सदस्य बना

चर्चा में क्यों?

पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते) 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आधिकारिक रूप से दक्षिण-पर्व एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) का 11वाँ सदस्य बन गया है।

औपचारिक रूप से इसका समावेश कुआलालंपुर में एक समारोह में हुआ, जो 1990 के दशक के बाद आसियान का पहला विस्तार है।

मुख्य बिंदु

- मुद्दे के बारे में:
 - पूर्वी तिमोर ने वर्ष 2011 में आसियान की सदस्यता के लिये आवेदन किया था, उसे वर्ष 2022 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया तथा 14 वर्षों के बाद वर्ष 2025 में उसे पूर्ण सदस्यता प्राप्त हुई।
 - इससे पहले आसियान में शामिल होने वाला अंतिम देश 1999 में कंबोडिया था।

प्रभाव:

सदस्यता से पूर्वी तिमोर को आसियान के

<u>मक्त व्यापार समझौतों</u> में भाग लेने, निवेश के अवसर प्राप्त करने और व्यापक क्षेत्रीय बाज़ार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में मदद मिलेगी।

पूर्वी तिमोर (तिमोर-लेस्ते)

- पूर्वी तिमोर जिसे तिमोर-लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण-पूर्व में तिमोर सागर, उत्तर में वेटार जलडमरूमध्य, उत्तर-पश्चिम में ओम्बाई जलडमरूमध्य और दक्षिण-पश्चिम में पश्चिमी तिमोर (इंडोनेशियाई प्रांत पूर्वी नुसा तेंगारा का हिस्सा) से घिरा है।
- पूर्वी तिमोर में तिमोर द्वीप का पूर्वी आधा हिस्सा शामिल है, **जिसका पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है।**



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से ज्डें







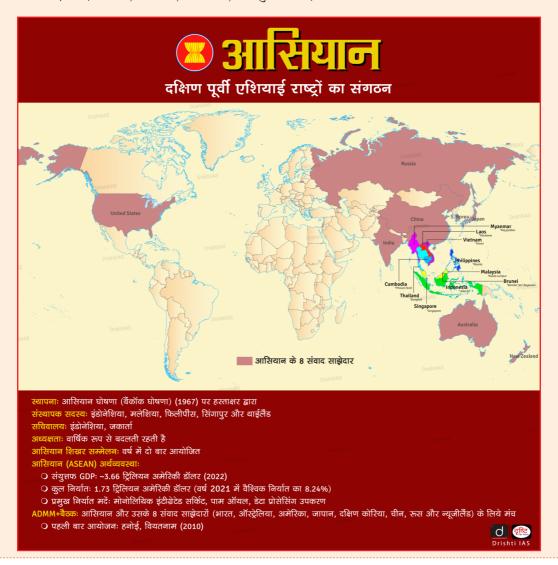




- 🍥 पूर्वी तिमोर, जिसे 18वीं शताब्दी मे<u>ं **पूर्तगाल ने उपनिवेश बनाया था**, पुर्तगाल के शासन के बाद वर्ष 1975 में इंडोनेशिया द्वारा कब्ज़ा</u> कर लिया गया, जिसके कारण यहाँ स्वतंत्रता के लिये एक लंबा संघर्ष चला।
- वर्ष 1999 में संयक्त राष्ट्र की निगरानी में हुए जनमत संग्रह में, पूर्वी तिमोरियों ने स्वतंत्रता के लिये मतदान किया, जिसके कारण शांति सेना के हस्तक्षेप तक हिंसा जारी रही और **वर्ष 2002 में संयक्त राष्ट्र द्वारा देश को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई।**

आसियान

- 💎 स्थापना: आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर द्वारा (1967)
- संस्थापक सदस्य: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड



'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













- 💎 **सचिवालय:** इंडोनेशिया, जकार्ता
- 💎 अध्यक्षता: वार्षिक रूप से बदलती रहती है (वर्तमान में मलेशिया)
- आसियान शिखर सम्मेलन बैठकः वर्ष में दो बार आयोजित

भौतिक वैज्ञानिक जयंत नार्लीकर को विज्ञान रत्न

चर्चा में क्यों?

प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक **जयंत विष्णु नार्लीकर को मरणोपरांत <u>विज्ञान रत्न पुरस्कार</u> 2025 के लिये चयनित** किया गया है, जो **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** में **आजीवन उपलब्धियों** के लिये देश का सर्वोच्च सम्मान है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के दूसरे संस्करण की घोषणा की, जिसमें चार श्रेणियों - विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री,
 विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में 23 व्यक्तियों तथा एक संस्थान को सम्मानित किया गया है।

मुख्य बिंद्

- 💎 जयंत विष्णु नार्लीकर के बारे में:
 - जयंत विष्णु नार्लीकर (1938–2025) एक प्रख्यात खगोल-भौतिक वैज्ञानिक थे, जो ब्रह्मांड विज्ञान, सामान्य सापेक्षता तथा ब्रह्मांड के स्थिर-अवस्था सिन्दांत पर अपने शोध कार्यों के लिये विख्यात थे।
 - सर फ्रेड होयल के निकट सहयोगी के रूप में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के होयल-नार्लीकर सिद्धांत का सह-विकास किया।
 - 🍥 वे पुणे स्थित अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल-भौतिकी केंद्र (IUCAA) के संस्थापक निदेशक रहे।
 - उनके योगदान ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के मध्य सेतु का कार्य किया, जबिक उनके लोकप्रिय विज्ञान लेखन ने युवा वैज्ञानिकों की अनेक पीढियों को प्रेरित किया।
- 💎 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्त्ताः

विज्ञान श्री (विशिष्ट योगदान)		
प्राप्तकर्त्ता	क्षेत्र	
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह	कृषि विज्ञान	
यूसुफ मोहम्मद शेख	परमाणु ऊर्जा	
के. थंगराज	जैविक विज्ञान	
प्रदीप थलप्पिल	रसायन विज्ञान	
अनिरुद्ध भालचंद्र पंडित	इंजीनियरिंग विज्ञान	
एस. वेंकट मोहन	पर्यावरण विज्ञान	
महान एम.जे.	गणित और कंप्यूटर विज्ञान	

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से ज्डें





UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयल कोर्म





जयन एन	अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
विज्ञान युवा (युवा वैज्ञानिक पुरस्कार)		
जगदीश गुप्ता कपुगंती	कृषि विज्ञान	
सतेंद्र कुमार मंगरौठिया	कृषि विज्ञान	
देबरका सेनगुप्ता	जैविक विज्ञान	
दीपा अगाशे	जैविक विज्ञान	
दिब्येंदु दास	रसायन विज्ञान	
वलीउर रहमान	भू - विज्ञान	
अर्काप्रवा बसु	इंजीनियरिंग विज्ञान	
सब्यसाची मुखर्जी	गणित और कंप्यूटर विज्ञान	
श्वेता प्रेम अग्रवाल	गणित और कंप्यूटर विज्ञान	
सुरेश कुमार	दवा	
अमित कुमार अग्रवाल	भौतिक विज्ञान	
सुरहुद श्रीकांत मोरे	भौतिक विज्ञान	
अंकुर गर्ग	अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी	
मोहनशंकर शिवप्रकाशम	प्रौद्योगिकी और नवाचार	
विज्ञान टीम पुरस्कार		
CSIR अरोमा मिशन	कृषि विज्ञान	

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार

💎 परिचयः

- ज राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नवप्रवर्तकों के असाधारण योगदान को मान्यता देता है।
- पदम पुरस्कारों की तर्ज़ पर स्थापित यह सम्मान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विविध क्षेत्रों में उपलिब्धियों को मान्यता देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें















- ्ये पुरस्कार **प्रतिवर्ष भारत के <u>राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस</u> पर राष्ट्रपति भवन** में प्रदान किये जाते हैं।
- 🍥 वर्ष 2023 में स्थापित इस पुरस्कार के विजेताओं की अनुशंसा **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार** की अध्यक्षता वाली **राष्ट्रीय विज्ञान** पुरस्कार समिति (RVPC) द्वारा की जाती है।
- इसका पहला समारोह अगस्त, 2024 में आयोजित किया गया था।

श्रेणियाँ:

- विज्ञान रतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिको के किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलिब्धियों और योगदान के लिये प्रदान किया जाता है।
- विज्ञान श्री: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये सम्मानित किया जाता है।
- विज्ञान युवा: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में *असाधारण उपलब्धियों* के लिये 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है।
- विज्ञान टीम: उत्कृष्ट सहयोगात्मक कार्य के लिये तीन या अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्त्ताओं या नवप्रवर्तकों की टीम को प्रदान किया जाता है।

त्रिशूल अभ्यास

चर्चा में क्यों?

भारत ने पाकिस्तान से सटी **पश्चिमी सीमा** पर बड़े स्तर पर तीनों सेनाओं क<u>ा संयुक्त अभ्यास 'त्रिशृल'</u> प्रारंभ किया है।

यह अभ्यास <mark>सर क्रीक क्षेत्र</mark> में बढ़ते तनाव के बीच किसी भी उकसावे या विरोध का सामना करने तथा **रक्षा तैयारियों को सुदृढ़** करने में भारत की तत्परता को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंद्

अभ्यास के बारे में:

- यह अभ्यास 30 अक्तूबर से 10 नवंबर, 2025 तक निर्धारित है, जिसमें सेना, नौसेना और वाय सेना की बड़े पैमाने पर भागीदारी शामिल है।
 - ् इसका उद्देश्य **परिचालन तत्परता, संयुक्त समन्वय** और **बह-क्षेत्र युद्ध कौशल** को बढ़ाना है।
- इस अभ्यास का कोड नाम "त्रिश्ल" है, जबिक आंतरिक रूप से इसे "महागुर्जर" कहा जाता है।
- यह अभ्यास **जैसलमेर (राजस्थान) से सर क्रीक (गुजरात)** तक फैले थार रेगिस्तान को कवर करेगा।

- मुख्य लक्ष्य **सेना, नौसेना और वायुसेना** के बीच **संयुक्त संचालन** का परीक्षण तथा सुधार करना है, जिसमें **भूमि, समुद्र, वायु** एवं साइबर क्षेत्र शामिल हैं।
- अभ्यास में एकीकृत संचालन, डीप-स्ट्राइक मिशन, अम्फीबियस युद्ध और बहु-क्षेत्र युद्ध तैयारियों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- यह अभ्यास विभिन्न कमांडों के बीच समन्वय बढ़ाने और नवीनतम स्वदेशी हथियार प्रणालियों को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में परखने का भी लक्ष्य रखता है।

भागीदारी:

🧓 सेना ने 20,000 से अधिक सैनिक तैनात किये हैं, जिन्हें T-90S और अर्जुन टैंक, हॉवित्ज़र, सशस्त्र हेलीकॉप्टर तथा मिसाइल प्रणाली का समर्थन प्राप्त है।

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें











- o वायुसेना (IAF) उच्च-गति वाले "महागुर्जर" संचालन कर रही है, जिसमें राफेल और सुखोई-30MKI फाइटर जेट, परिवहन तथा ईंधन भरण विमान (IL-78), AEW&C प्रणाली एवं UAVs तैनात हैं।
- **नौसेना** ने सौराष्ट्र और गुजरात तटों पर **फ्रिगेट** तथा **विध्वंसक पोत** तैनात किये हैं, ताकि अम्फीबियस एवं समुद्री युद्ध अभ्यास किया जा सके।
- एयरमैन को नोटिस (NOTAM) :
 - भारतीय वाय सेना (IAF) ने अभ्यास के दौरान राजस्थान और गुजरात के बड़े हिस्सों में **नागरिक उड़ानों को प्रतिबंधित करने के** लिये एयरमैन को नोटिस (NOTAM) जारी किया है, जबकि पाकिस्तान ने 28-29 अक्तूबर 2025 के आसपास अपने केंद्रीय तथा दक्षिणी वायु क्षेत्र में समान रूप से हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगाया है, संभवत: अपने सैन्य अभ्यास या हथियार परीक्षण के कारण।

मोंथा चक्रवात

चर्चा में क्यों?

बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात "मोंथा" भारत के पूर्वी तट के निकट पहुँचते ही तीव्र रूप ले रहा है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु

- चक्रवात के बारे में:
 - परिभाषा: चक्रवात वे तेज वायु-संचलन हैं, जो निम्न-दबाव क्षेत्रों के चारों ओर घूमते हैं, जो उत्तरी गोलार्ब्स में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ब्ह में दक्षिणावर्त घूमता है। ये अक्सर तूफान और गंभीर मौसम उत्पन्न करते हैं।
 - चक्रवातों का वर्गीकरण: IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव वाली प्रणालियों को क्षिति क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है।
 - चक्रवातों का नामकरण: WMO/ESCAP (एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग) का ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल, जिसमें 13 उत्तरी <mark>हिंद महासागर</mark> देश शामिल हैं, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के नामकरण का प्रबंधन करता है।
 - ् पैनल के पास 13 देशों द्वारा प्रस्तुत नामों की पूर्व-निर्धारित सूची होती है, जिसका क्रमिक रूप से उपयोग किया जाता है।
 - ् नामों का चयन स्तंभ दर स्तंभ किया जाता है, चाहे चक्रवात कहीं भी उत्पन्न हुआ हो।
- हालिया चक्रवातः
- 'मोंथा' नाम, जिसका अर्थ है सुंदर या सुगंधित फूल, थाईलैंड द्वारा दिया गया था।
- इस मौसम के पहले चक्रवाती तूफान का नाम श्रीलंका के सुझाव पर 'शक्ति' रखा गया।
- हाल ही में आए अन्य चक्रवातों में **शक्ति** (श्रीलंका), **फेंगल** (सऊदी अरब), **दाना** (कतर), **असना** (पाकिस्तान) और **रेमल** (ओमान) शामिल हैं।
- नामकरण सूची के अनुसार, अगला चक्रवात **सेंयार (UAE) होगा,** उसके बाद **दित्वा (यमन), अर्नब (बांग्लादेश)** और **मुरास्** (भारत) होंगे।

टिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













DFC पर यात्री ट्रेनों का परिचालन

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है।

मुख्य बिंदु

- पारंपिरक रूप से, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) विशेष रूप से माल पिरवहन के लिये विकसित किये गए थे, जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाना और मौजूदा रेलवे लाइनों पर भीड़ को कम करना था।
- हालाँकि छठ पूजा (25-28 अक्तूबर, 2025) के दौरान भारी भीड़ के कारण, रेलवे ने पहली बार खाली पैसेंजर कोचिंग रैक और विशेष ट्रेनों को DFC पर चलाने की अनुमित दी।
- 💎 इस कदम से त्योहार के समय अधिक संख्या में **पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें** संचालित करना संभव हुआ।

DFC का स्वरूप:

- ईस्टर्न DFC (EDFC): ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना (पंजाब) से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए दनकुनी (पश्चिम बंगाल) तक लगभग 1,839 किमी की लंबाई में विस्तृत है। EDFC का अधिकांश वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।
- वेस्टर्न DFC (WDFC): यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (JNPT), मुंबई से दादरी तक लगभग 1,506 किमी लंबा है। WDFC का वित्तपोषण जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा किया जा रहा है।

8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तें स्वीकृत

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिये संदर्भ की शर्तों (ToR) को स्वीकृति दे दी है।

यह आयोग केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संरचना तथा सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा एवं सिफारिश करने
 के लिये उत्तरदायी है।

मुख्य बिंदु

- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की घोषणा जनवरी, 2025 में की गई थी और इसके संदर्भ की शर्तों (ToR) को 28 अक्तूबर, 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (रक्षा कार्मिकों सिहत) एवं 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
- 💎 आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद **संशोधित वेतन एवं पेंशन संरचना जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर मॉड्यूस कोर्म





8वें केंद्रीय वेतन आयोग की संरचना:

पद	नाम / पदनाम
अध्यक्ष	न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई (पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश)
अंशकालिक सदस्य	प्रो. पुलक घोष (भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलूरू)
सदस्य सचिव	पंकज जैन (पेट्रोलियम सचिव)

संदर्भ की शर्तें (ToR):

- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के बाद सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है:
 - ्रदेश की आर्थिक स्थिति एवं **राजकोषीय सतर्कता** की आवश्यकता।
 - विकासात्मक व्यय एवं **कल्याणकारी उपायों** के लिये संसाधनों की उपलब्धता।
 - गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्तपोषित लागत (विशेषकर 2004 से पूर्व की पेंशन देयताएँ)।
 - राज्य के वित्त पर प्रभाव, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर अपने वेतनमान को केंद्र के अनुरूप करती हैं।
 - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSU) एवं निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की वर्तमान पारिश्रमिक संरचना, लाभ तथा कार्य स्थितियाँ।

पृष्ठभूमि:

- वेतन आयोग का **गठन** आमतौर पर **प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार किया** जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के भत्ते, वेतन संरचना एवं पेंशन में बदलाव की समीक्षा तथा सिफारिश की जा सके।
- 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वाँ मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है।

मुख्य बिंदु

परिचय:

- वं 24 नवंबर, 2025 को न्यायमुर्ति बी. आर. गवई के उत्तराधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और 10 फरवरी, 2027 तक लगभग 15 माह का कार्यकाल पूरा करेंगे।
- वह हरियाणा से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे।
- वह पहली पीढ़ी के वकील हैं, जो अपनी स्पष्ट टिप्पणियों, संतुलित निर्णयों और संवैधानिक नैतिकता पर ज़ोर देने के लिये जाने जाते हैं।
- उनके कार्यकाल में **न्यायिक सुलभता, <mark>प्रशासनिक सुधार</mark> और संवैधानिक व्याख्या में स्थिरता** पर विशेष ध्यान दिये जाने की संभावना है।



रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें













💎 महत्त्वपूर्ण निर्णय:

- अनुच्छेद 370: पाँच-सदस्यीय पीठ के सदस्य रहे, जिसने अनुच्छेद 370 के निरसन को वैध ठहराया।
- 🧑 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा: इस संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णय देने वाली पीठ का हिस्सा रहे।
- चुनाव आयोग की निगरानी: वर्तमान में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की देखरेख करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर भारल्लेकैं मुख्य न्यायाधीश:
- अनुच्छेद 124 (2) के तहत मुख्य न्यायाधीश सिहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा की जाती है।
- विरिष्ठतम न्यायाधीश को सेवा की अविध के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है (यह परंपरा है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं)।
- अर्हता: मुख्य न्यायाधीश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को
 - ् भारत का नागरिक होना चाहिये,
 - ् कम-से-कम **5 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** या
 - ् 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिये,
 - ् अथवा राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिये।
- 💎 मुख्य न्यायाधीश को **केवल <u>संसद</u> के दोनों सदनों में <mark>विशेष बहुमत</mark> से पारित प्रस्ताव के पश्चात् ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।**

राष्ट्रीय एकता दिवस

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल के भारत के एकीकरण में योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। ▼ वर्ष 2025 में यह दिवस विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि यह सरदार पटेल की 150वीं जयंती का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु

💎 राष्ट्रीय एकता दिवस:

- यह दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा प्रतिपादित एकता, अखंडता और समावेशिता के मूल्यों का प्रतीक है।
- इसे पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था, जब सरकार ने राष्ट्र-निर्माण में पटेल के ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने का निर्णय लिया।
- वर्ष 2015 के आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विभिन्न
 राज्यों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और परस्पर जुड़ाव को सशक्त करना था।

💎 कार्यक्रमः

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा माई भारत मंच के माध्यम से आयोजित सरदार @150 एकता यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभिक्त तथा नागरिक दायित्व की भावना को बढ़ावा देना था, जो 'एक भारत, आत्मिनर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- इसके अतिरिक्त, 31 अक्तूबर, 2025 को देश के प्रमुख शहरों में "रन फॉर यूनिटी" नामक राष्ट्रव्यापी दौड़ का आयोजन किया गया,
 जिसका शुभारंभ नई दिल्ली से हुआ।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्मेस



IAS करेंट अफेयर





- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी:
 - 31 अक्तूबर, 2018 को सरदार पटेल की स्मृति में 182 मीटर (600 फीट) ऊँची विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा स्टैच्य ऑफ युनिटी का उद्घाटन गुजरात के केवडिया में किया गया।
 - यह प्रतिमा नर्मदा नदी के तट पर, सरदार सरोवर बाँध (जो कंक्रीट की मात्रा के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्व बाँध है) के समीप साधु बेट पहाड़ी पर स्थित है।
 - वर्ष 2020 में इसे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के "आठ अजुबों" की सूची में भी शामिल किया गया था।







- भारत के पहले गृहमंत्री तथा उप-प्रधानमंत्री
- बारदोली की महिलाओं द्वारा 'सरदार' की उपाधि दी गई

- 🗘 प्रिंचके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इनकी स्मृति में गुजरात में वर्ष 2018 में 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया गया।

संविधन सभा की समितियाँ जिनकी अध्यक्षता सरदार वल्लम भाई पटेल ने की 🥏

- मूल अधिकारों पर सलाहकार समिति
- अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं वंचित क्षेत्रों पर समिति
- प्रांतीय गठन समिति

- खंडा (1918) तथा बारदोली (1928) आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ
- कॉन्ग्रेस के 46 वें अधिवेशन (मार्च 1931) की अध्यक्षता करते हुए गांधी-इरविन समझौते की पुष्टि का आह्वान किया।
- इन्हें 'भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत' के रूप में याद किया जीता है क्योंकि इन्होने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की।
- िइन्होंने लगभग 565 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके चलते इन्हें भारत का लौह पुरुष' के रूप में जाना गया।

'दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें











हष्टि लर्निंग

